● वर्ष : 17 ● अंक : 122 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का सम्मान

दिल्ली से प्रकाशित गुरुवार 19 फरवरी 2026

तकनीक केवल कार्य को समाप्त नहीं करती बल्कि उसके स्वरूप को बदलती है: पीएम

शुरुआती उपयोगकर्ताओं तक सीमित ना रहे एआई, इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचे

एजेंसी। नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को मानव-केंद्रित बनाने को लेकर कहा कि इस तकनीक के लाभ सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए, न कि केवल शुरुआती उपयोगकर्ताओं तक सीमित रहना चाहिए। उन्होंने यह बात बुधवार को एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसमें आगामी एआई इम्पैक्ट समिट पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सोच में भारत के लिए एआई की रणनीति तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है- सार्वभौमिकता, समावेशिता और नवाचार। उनका मानना है कि भारत को केवल एआई का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि इसे बनाने और विकसित करने वाला शीर्ष तीन देशों में शामिल होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने युवाओं की चिंता को समझते हुए कहा कि एआई के कारण रोजगार के स्वरूप में बदलाव होना एक वास्तविक चिंता है। उन्होंने कहा कि तैयारी ही भय का सबसे अच्छा इलाज है। इसी कारण हम अपने लोगों को एआई-उन्मुख भविष्य के लिए कौशल और पुनःकौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने

जोर देकर कहा कि तकनीक केवल कार्य को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसके स्वरूप को बदलती है और नई तरह की नौकरियां पैदा करती है। पीएम मोदी ने एआई को एक "शक्ति-वर्धक" के रूप में देखा, जो मानव क्षमताओं को नए स्तर तक बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन से भारत की अर्थव्यवस्था में नई तकनीकी नौकरियां भी उत्पन्न होंगी। एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के विषय को उन्होंने लोग, ग्रह और प्रगति के रूप में बताया और कहा कि एआई का उद्देश्य केवल नवाचार नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाना होना चाहिए। मोदी ने कहा कि एआई सिस्टम ज्ञान और डेटा पर आधारित होते हैं जो पूरी दुनिया में उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसके लाभ केवल कुछ विशेष लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि एआई इम्पैक्ट समिट-2026 पहली बार ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन आवाजों और विकास प्राथमिकताओं को बढ़ावा देना है जो अक्सर कम प्रतिनिधित्व वाली रहती हैं। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में एआई के अनुप्रयोग पर उदाहरण देते हुए बताया कि अमूल ने एआई का इस्तेमाल कर 36 लाख महिला डेयरी किसानों को उनके गांवों में पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता संबंधी मार्गदर्शन दिया। मोदी ने कहा कि जहां पूरी दुनिया एआई के कारण असमानताओं की चिंता कर रही है, भारत इसे कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एहतियात और मानव नियंत्रण पर जोर देते हुए कहा कि एआई का इस्तेमाल मानव क्षमता बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि निर्णय लेने में इसे पूर्ण रूप से शामिल करने के लिए। उन्होंने इंडियाएआई सुरक्षा संस्थान की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने एथिकल और सुरक्षित एआई के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एआई के संभावित खतरों और नुकसान से बचने के लिए दुनिया भर में एक साझा समझ विकसित करना जरुरी है। इसमें मानव निगरानी, सुरक्षा-डिज़ाइन, पारदर्शिता और गहरी नकली सामग्री, अपराध और आतंकवाद में एआई के इस्तेमाल पर रोक जैसे सिद्धांत शामिल होने चाहिए। पीएम मोदी ने निष्कर्ष में यह कहा कि भारत का दृष्टिकोण स्थानीय जोखिमों और सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई को सभी के लिए सुरक्षित और समावेशी बनाते हुए नवाचार को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने की स्पेन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता, परस्पर संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन से इतर स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और स्पेन के बीच सहयोग को अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट से इतर यहां द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने के लिए कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठक में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन पर क्रियान्वयन, और शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज को भारत-यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए उनका लगातार सहयोग देने के लिए सराहना की।

एआई को जिम्मेदार बनाने का 24 घंटे में 2.5 लाख ने किया संकल्प, बना विश्व रिकॉर्ड

एजेंसी। नई दिल्ली

इंडिया एआई मिशन और इंटेल इंडिया ने नई दिल्ली में इंडिया एआई एम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटों में सबसे अधिक संकल्प का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। इस दौरान 2.5 लाख से अधिक लोगों ने 16-17 फरवरी के बीच नैतिक और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को भारत मंडपम में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा के बाद कहा कि यह 'जिम्मेदार एआई' की दिशा में भारत की प्रगति में बड़ी उपलब्धि है। वैष्णव ने एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग में युवाओं को शामिल करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा, "यह उनका ही दृष्टिकोण है जिसने हमें कॉलेजों से संपर्क करने, शिक्षकों से बातचीत करने और छात्रों को एआई को समाज की भलाई का एक उपकरण बनाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के अवसर पर आज भारत मंडपम में पत्रकार वार्ता में आधिकारिक निर्णायक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रवीण पटेल ने रिकॉर्ड की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक नियमावली के तहत संकल्प लेने को प्रोत्साहित किया गया था। हमने रिकॉर्ड के लिए 5 हजार की सीमा रखी थी लेकिन 24 घंटे में 2,50,946 ने संकल्प लेकर यह रिकॉर्ड बनाया है।

संक्षिप्त समाचार

ईसीआई का ऐलान, राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान

नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की ऐलान कर दिया। राज्यसभा के 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। ईसीआई के मुताबिक 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच मतदान किया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी। चुनावों के लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव होना हैं। महाराष्ट्र की 7 सीटें, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, ओडिशा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2, जबकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए यह चुनाव कराया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तिरुचि शिवा, साकेत गोखले, रामदास अठावले, अभिषेक मनु सिंघवी, शरदचंद्र गोविंदराव पवार, भगवत किशनराव कराड, ममता मोहंता, रामेश्वर तेली, इंदु बाला गोस्वामी, कवि तेजपाल सिंह तुलसी, एनआर एलंगो, अमरेंद्र धारी सिंह और किरण चौधरी का राज्यसभा सदस्य के रूप में वर्तमान कार्यकाल अप्रैल में पूरा होगा।

जिनेवा वार्ता के बीच अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट ईरान के लिए रवाना किए

जिनेवा। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम होने की उम्मीदें अभी जगी ही थीं कि वाशिंगटन के एक नए सैन्य कदम ने क्षेत्र में युद्ध की आशंकाओं को फिर से हवा दे दी है। एक ओर जहां दोनों देश परमाणु मुद्दे और आर्थिक प्रतिबंधों पर मेज पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने पिछले 24 घंटों के भीतर ईरान की सीमाओं के करीब 50 से अधिक अत्याधुनिक फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। सैन्य विशेषज्ञों और स्वतंत्र फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, इन विमानों में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान माने जाने वाले एफ-22 रैप्टर, एफ -35 लाइटनिंग और एफ -16 शामिल हैं। इन लड़ाकू विमानों के साथ एरियल रिफ्यूलिंग टैंकरों की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि अमेरिकी वायुसेना किसी बड़े और लंबी दूरी के ऑपरेशन की तैयारी में है। सैन्य बेड़ों की इस आक्रामक आवाजाही की पुष्टि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने भी की है। उनके अनुसार, अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी हवाई और समुद्री मारक क्षमता को और अधिक मजबूत करने में जुटा है। केवल आसमान ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी घेराबंदी सख्त कर दी गई है। यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो पहले कैरिबियन क्षेत्र में था, अब अटलांटिक को पार कर तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। इस विशाल युद्धपोत के साथ तीन गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर—यूएसएस महान, यूएसएस बैनब्रिज और यूएसएस विंस्टन चर्चिल भी तैनात किए गए हैं।

सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की मुलाकात भारत में एआई के विकास पर की चर्चा

एजेंसी। नई दिल्ली

एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने से पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से बुधवार को मुलाकात की और भारत में एआई के विकास पर चर्चा की। इस बैठक के बारे में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के साइडलाइन में सुंदर पिचाई से मुलाकात करना सुखद अनुभव रहा। हमने एआई क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों और इस क्षेत्र में हमारे प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों के साथ गूगल किस प्रकार सहयोग कर सकता है, इस बारे में चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पिचाई ने एक्स पर पोस्ट किया था- एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ, समिट में

गुरुवार को पीएम मोदी उद्घाटन भाषण देंगे, जो वैश्विक सहयोग और समावेशी एवं जिम्मेदार एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को दिशा देगा। इस समिट में 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख और 60 मंत्री एवं उपमंत्रियों सहित 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा सीईओ, संस्थापक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, सीटीओ और परोपकारी संगठनों सहित 500 से ज्यादा वैश्विक एआई अग्रणी भी इसमें शामिल होंगे।

विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने वैश्विक साझेदारी के साथ दिखाई समुद्री ताकत

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत ने 1971 के युद्ध में जिस जगह में पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को डुबो दिया था, वहीं एक बार फिर इतिहास की गूंज सुनाई दी। विशाखापत्तनम के उसी ऐतिहासिक किनारे पर बुधवार को भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री ताकत, व्यावसायिकता और वैश्विक साझेदारी का प्रदर्शन किया है। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को देखा और भरोसा जताया कि इस फ्लीट रिव्यू में शामिल सभी नौसेनाएं मिलकर समुद्रों को दुनिया भर के विकास, खुशहाली और पूरी भलाई के रास्ते के तौर पर

राष्ट्रपति मुर्मु ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू देखकर समुद्री परंपराओं पर भरोसा जताया

आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समुद्री परंपराओं के लिए देशों के बीच एकता, भरोसा और सम्मान दिखाता है। समुद्रों के साथ भारत का रिश्ता गहरा और हमेशा रहने वाला रहा है। सदियों से ये समुद्र भारत के लिए कॉमर्स, कनेक्शन और कल्चरल लेन-देन के रास्ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र समेत इंटरनेशनल रिश्तों को लेकर भारत का नजरिया 'वसुधैव कुटुम्बकम' या 'दुनिया एक परिवार है' की हमारी सोच को दिखाता है। उन्होंने सभी भारतीयों की ओर से मित्र देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों और नाविकों को बधाई देते हुए कहा कि आप अपनी सेवाओं से अपने देशों की सबसे अच्छी परंपराओं को दिखाते हैं। नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि यह भारत में किया गया तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है। आज हमने इस समुद्री समीक्षा में 70 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स को हिस्सा लेते देखा है, जिसमें 18 दूसरे देशों के 19 जहाजों के साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज शामिल हैं। इस साल भारत के फ्लीट रिव्यू में पहली बार देसी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत हिस्सा ले रहा है। हमने मोबाइल कॉलम में देसी कलवरी-क्लास सबमरीन को भी हिस्सा लेते देखा है।

अरुणाचल और नागालैंड के जंगलों में आग बुझाने सेना-वायुसेना का युद्धस्तर पर काम जारी

गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के जंगल में आग बुझाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। भारतीय सेना और वायुसेना ऑपरेशन में जुटी है। हेलीकॉप्टर लगातार पानी गिरा रहे हैं, जबकि सतह पर टीमें खास उपकरणों से आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। अब तक अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में आग पर काबू पाया जा चुका है। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हेलीकॉप्टर दो मोर्चों पर जंगल की आग बुझाने के मिशन में लगे हैं और मुश्किल इलाकों में लगातार हवाई फायरफाइटिंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना ने जानकारी दी है कि अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में कुल 139,800 लीटर पानी गिराया गया है, जिससे आग बुझ गई है। साथ ही नागालैंड में जुकोऊ घाटी में ऑपरेशन जारी है, जिसमें हेलीकॉप्टर से पानी लाकर जप्फू पीक के पास खड़ी ढलानों, खराब विजिबिलिटी और दुर्लभ हवा के बीच आग बुझा रहे हैं।

बंगाल में ममता बनर्जी तुगलक और औरंगजेब की तरह शासन चला रही हैं : गिरिराज सिंह

एजेंसी। पटना

पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर द्वारा बनाई जा रही बाबरी मस्जिद पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में एनडीए के नेताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी भी कबीर का साथ दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दों पर भी बंगाल सरकार की भूमिका पर सवाल उठते हैं और ममता को डबल गेम नहीं खेलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी मुसलमानों के सहारे सत्ता में बनी रहना चाहती हैं, लेकिन अब बंगाल के हिंदू जाग चुके हैं। जो लोग ममता बनर्जी को 'शेरनी' कहते हैं, वे उन्हें गलत बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि वे राज्य को बांग्लादेश बनाने की दिशा में ले जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तुगलक और औरंगजेब की तरह शासन चला रही हैं और हिंदुओं को दबाने का काम कर रही हैं। वहीं बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत दर्ज की है और अब बंगाल में भी पार्टी का झंडा लहराएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। इधर बिहार की राजनीति में भी बयानबाजी तेज है। बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वे अपने कार्यकाल का हिसाब दें।

मोदी से मिलकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा- जय हो!

एजेंसी। मुंबई

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मुलाकात की। मुंबई के लोक भवन में मंगलवार को वार्ता और संवादताता सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एक ही कार में दिखे। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोस्ताना बातचीत की। राष्ट्रपति मैक्रों ने मंगलवार देररात कार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ यात्रा का फोटो एक्स पर साझा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लिखा, ''जय हो!'' उल्लेखनीय है कि भारत और फ्रांस ने मंगलवार को अपने रिश्तों को एक और नई ऐतिहासिक ऊंचाई दी है। दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' में बदल दिया है। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच हुई बैठक में रक्षा, तकनीक, स्टार्टअप, जरूरी खनिज, स्वास्थ्य

और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई बड़े एलान हुए। राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे के दौरान रक्षा क्षेत्र में कई अहम फैसले हुए। कर्नाटक के वेमागल में 'एच125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन' का उद्घाटन हुआ। यह भारत में निजी क्षेत्र की पहली हेलीकॉप्टर फैक्टरी होगी। इसे टाटा और एयरबस मिलकर चलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट तक उड़ान भर सकेगा। दोनों देशों ने तय किया है कि अब हर साल विदेशमंत्रियों के बीच बातचीत होगी। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'इंडिया-फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क' शुरू किया गया। तकनीक और अन्यक्षेत्र में सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने पिछले साल की अपनी फ्रांस यात्रा को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्सिले शहर का जिक्र किया, जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी दिखाई थी। उन्होंने वीर सावरकर को भी याद किया, जिन्होंने इसी शहर में अंग्रेजों की कैद से बचने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। इस अवसर पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले 52वें जी-7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैक्रों ने कहा कि शिखर सम्मेलन से पहले भारत और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय एजेंडा पर समझौता करने के लिए अस्थायी बैठक होनी चाहिए।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

भारतीय सेवाओं में आरक्षण? जाति जनगणना की मांग बेमानी नहीं

हाल ही में राज्यसभा में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जो जानकारी राज्यसभा में दी गई है। उसके आंकड़ों ने एक बार फिर भारतीय प्रशासनिक ढांचे में प्रतिनिधित्व के सवाल को विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में अखिल भारतीय सेवाओं—आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों की सामाजिक श्रेणीवार जानकारी संख्या के साथ प्रस्तुत की है। यह आंकड़े सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 01 जनवरी, 2025 की स्थिति में आईएएस के 6877 पद में 5577 की नियुक्ति है। इसमें ओबीसी के 245, एससी के 135, एसटी के 67 अधिकारी हैं। 1300 पद खाली पड़े हैं। 5577 पदों में 5130 पद सामान्य वर्ग के हैं। एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग के मात्र 447 अधिकारी हैं। इसका मतलब है यूपीएससी की नियुक्ति में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। 1300 पद खाली हैं। इसके बाद भी आईएएस के पदों के समकक्ष सरकार संविदा में नियुक्ति कर रही है। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बात कही थी। उक्त आंकड़े उनकी बात की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेवा में जो अधिकारी नियुक्त हैं आरक्षण होने के बाद भी एसटी ,एससी और ओबीसी वर्ग की जातियों को प्रति निधित्व नहीं मिला है।

आंकड़ों के अनुसार स्वीकृत पदों और वास्तविक तैनाती में भारी अंतर है। भारतीय सेवा में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का चयन यूपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होती है। उस नियुक्ति में आरक्षित वर्ग जिसमें पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों की हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह स्थिति तब है, जब संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था, लागू है। आरक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे में सामाजिक न्याय और समावेशिता सुनिश्चित करने का संवैधानिक प्रावधान है। प्रश्न यह नहीं है, किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है या कम है। प्रश्न यह है आरक्षण की नीति अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर पा रही है? यदि हजारों पद वर्षों तक रिक्त पड़े हैं। जो नियुक्तियां की गई है उनमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। स्वाभाविक है, इससे आरक्षित वर्गों की भागीदारी प्रभावित होगी। रिक्तियों को समय पर न भरना, नियुक्ति करते समय आरक्षण का पालन नहीं करना, केवल प्रशासनिक अक्षमता का मामला नही है। यह सामाजिक एवं राजनीतिक संतुलन से भी जुड़ा है। राहुल गांधी जिस तरह से जाति जनगणना की मांग मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी और विपक्षी दलों की इस मांग को खारिज करना तर्कसंगत नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में 80:20 को लेकर हिंदुओं और धार्मिक संदर्भ में धुव्रीकरण का जो प्रयास हुआ है। यदि हिंदुओं के एक बहुत बड़े वर्ग जिसमें एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में 80% हिंदुओं को एकजुट नहीं रखा जा सकता है। नीति निर्माण सटीक आंकड़ों और पारदर्शिता पर आधारित होना चाहिए। यदि सरकार के पास अद्यतन और विस्तृत सामाजिक-आर्थिक डेटा उपलब्ध नहीं होगा,तो सरकार समान प्रतिनिधित्व, अवसरों और संसाधनों के वितरण पर किस तरह से प्रभावी निर्णय ले सकेगी? जाति जनगणना का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति को समझना और नीति को अधिक न्यायसंगत बनाना है। जाति जनगणना को राजनीतिक दलों को हथियार नहीं बनना चाहिए। जाति जनगणना के आंकड़ों का उपयोग बेहतर सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इतना संवेदनशील मामला भावनात्मक या टकरावपूर्ण बहस में ना बदला जाए। नाही इसका राजनीतिक कारणों में उपयोग होना चाहिए।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

ख़ास ख़बर

डीसीडब्ल्यू के निष्क्रिय रहने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के लंबे समय से काम नहीं करने और आयोग के चेयरपर्सन का पद जनवरी, 2024 से खाली होने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने महिला आयोग के लंबे समय से ठप्प रहने पर गहरी चिंता जताई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सत्यम सिंह राजपूत ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद दिल्ली महिला आयोग कार्यशील नहीं है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटित हो रहे हैं। ऐसे में बिना चेयरपर्सन के दिल्ली महिला आयोग को कैसे छोड़ा जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करने को कहा है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सांसद सुधाकर सिंह ने दायर याचिका में कहा है कि दिल्ली महिला आयोग में कोई काम नहीं होता। न तो वहां कोई हेल्प डेस्क कार्यरत है और न ही कोई अधिकारी या स्टाफ, महिलाओं की शिकायतों को सुनने वाला है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग कार्यदिवस के दौरान बंद रहता है जिसकी वजह से पारिवारिक काउंसलिंग या रेप क्राईसिस सेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग का कार्यशील नहीं होना महिलाओं को न्याय और सुरक्षा पाने के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में महिलाओं के साथ देश भर में सर्वाधिक मामले दर्ज होते हैं लेकिन उसके बावजूद दिल्ली महिला आयोग का कार्यशील नहीं होना गंभीर बात है। याचिका में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि दिल्ली महिला आयोग को एक तय समय-सीमा में कार्यशील बनाया जा सके और महिलाओं की शिकायतों का निपटारा किया जा सके। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली महिला आयोग में चेयरपर्सन के खाली पड़े पद को तुरंत भरा जाए और आयोग में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की जाए।

शेयर बाजार की साख में बट्टा लगा रहा है डिब्बा ट्रेडिंग

» पैसा वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं मूंगिपा इन्वेस्टमेंट के निवेशक

लोकतंत्र की शान :नयी दिल्ली। मध्यम वर्ग के लोग कम समय में ज्यादा पैसे की चाहत में मेहनत से हासिल की गई अपनी गाढ़ी को अवैध तरीके से शेयर बाजार के समांतर खड़े हो चुके डब्बा ट्रेडिंग के जाल में फंसकर पलभर में गंवा दे रहे हैं। मूंगिपा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में निवेश का ऐसा ही एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मूंगिपा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के निदेशकों सुधीर, मधुर और शिवकुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और सामाजिक दायरे के लोगों को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ऑफ मार्केट, डिब्बा सिस्टम में फंसाया। जब पीड़ितों ने न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया तो उन्हें हर स्तर पर विफलता का सामना करना पड़ा। यहां तक कि पुलिस ने दस्तावेजी सबूत नहीं होने का हवाला देकर एफआईआर तक दर्ज करने से इनकार कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को हालिया समाप्त हुए संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में भी उठाया गया था, जहां डिब्बा ट्रेडिंग के सन्दर्भ में मूंगिपा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का नाम स्पष्ट रूप से सामने आया। इसके बावजूद आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि सेबी ने क्या कार्रवाई की। निवेशकों का आरोप है कि मूंगिपा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ सहित कई राज्यों से जुड़े रिश्तेदारों को अधिक धन का लालच देकर उनके पैसों को औपचारिक बैंकिंग और डीमैट चैनलों के बजाय नकद रूप में इकट्ठा किया। शिकायतों के अनुसार इस धन का उपयोग कथित रूप से शेयर बाज़ार निवेश के बजाय सट्टेबाज़ी, जुए और निजी खर्चों में किया गया, जबकि निवेशकों को फर्जी रिटर्न स्टेटमेंट दिखाकर गुमराह किया गया। निवेशक पिछले लंबे समय से अपनी रकम वापस पाने के लिए निदेशकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संबंधित निदेशक अपने आवासों से गायब हैं और संपर्क से बचते फिर रहे हैं। यह भी आरोप है कि लेन-देन को जानबूझकर कैश और परतदार तरीकों से किया गया, जिससे नियामक एजेंसियों जैसे सेबी, ईडी और सीबीआई की निगरानी से बचा जा सके। बढ़ती शिकायतों के बीच अब निवेशकों और सामाजिक संगठनों द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग तेज़ हो गई है।

मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खातों का आडिट करने की मांग पर दिल्ली सरकार को नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खातों का आडिट करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करने का आदेश दिया। याचिका एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एडुकेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों का लगातार आडिट करने के प्रावधान का पालन करने में विफल रही है।

दिल्ली पुलिस सप्ताह में बच्चों ने रंगों और शब्दों से बढ़ाया भरोसा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। बाहरी जिला पुलिस ने 'दिल्ली पुलिस सप्ताह–2026' के तहत स्कूलों में रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस और युवाओं के बीच रिश्तों को मजबूत करने की पहल की। बाहरी जिले के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बुधवार को बताया इस साल के कार्यक्रम की थीम रही "रचनात्मकता और समुदाय की साझेदारी से भरोसे का निर्माण है"।

चित्रकला प्रतियोगिता में दिखा उत्साहः पुलिस उपायुक्त के अनुसार पश्चिम विहार ईस्ट थाना क्षेत्र के सर्वोदय को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के विषय थे "नो योर पुलिस" और "पुलिस के साथ त्योहार"। बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी पेंटिंग के जरिए पुलिस की भूमिका, जनसहभागिता और सुरक्षा के संदेश को खूबसूरती से उकेरा। चित्रों में भरोसा, सुरक्षा और पुलिस–जनता की साझेदारी साफ नजर आई। वहीं इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित किया। पुलिस उपायुक्त के अनुसार रानी बाग थाना क्षेत्र के जीएसवी, सी-ब्लॉक, सरस्वती विहार में निबंध प्रतियोगिता कराई गई। विद्यार्थियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज के साथ पुलिस की सहभागिता पर अपने विचार रखे। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराना और उनके मन में विश्वास पैदा करना है।

भाजपा ने कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर लगाया सरकारी संपत्ति हड़पने का आरोप

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर सरकारी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग सलाखों के पीछे जाएं। भाजपा मुख्यालय में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक की कांग्रेस सरकार नागरिक सुविधाओं के लिए आवंटित 24 भूखंडों को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के रूप में परिवर्तित कर रही है। ये 24 भूखंड कांग्रेस भवन ट्रस्ट को हस्तांतरित किए गए हैं। इनका मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस इसे मात्र 2 करोड़ रुपये में हासिल कर रही है। 48 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में हमने देखा था कि कांग्रेस ने किस तरह से सरकारी संपत्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना लिया। इसी तरह रॉबर्ट वाड्रा, किसानों की जमीन हड़प कर उस पर निजी व्यवसाय करते हैं। अब अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 'कांग्रेस भवन' को ट्रस्ट को दे दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में करीब दो दर्जन सरकारी जमीनें, जिनका उपयोग कर्नाटक की जनता के लिए सिविक एमेनिटीज के रूप में होना था, इन जमीनों का उपयोग कांग्रेस भवन बनाने के लिए किया जा रहा है।

डॉ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में स्पोर्टस मीट-अस्तित्व 2026 का भव्य आयोजन किया गया जा रहा है

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः डॉ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में आज स्पोर्ट्स मीट "अस्तित्व 2026" का भव्य उद्घाटन किया गया। यह खेल प्रतियोगिता 16 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों की टीमों ने भाग लिया है, जो अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इस अवसर पर माननीय चेयरपर्सन श्रीमती अलका दास गुप्ता, माननीय अध्यक्ष श्री विराज सागर दास, माननीय उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास तथा माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती देवांषी दास ने संस्थान के सभी फैकल्टी सदस्यों, स्टाफ तथा छात्र-छात्राओं को अपने कुशल मार्गदर्शन और समर्थन के साथ हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उद्घाटन समारोह में डॉ. विजय धीर (डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन), प्रो. डॉ. निरंजन भट्टाचार्य (निदेशक), श्री बी.एम.के. गुप्ता (डायरेक्टर फाइनेंस), श्रीमती पंखुड़ी अग्रवाल (असिस्टेंट डायरेक्टर – एच.आर.) सहित सभी विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, फैकल्टी सदस्य एवं स्टाफ उपस्थित रहे। संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. निरंजन भट्टाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि खेल छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि खेलों में नियमित भागीदारी से शरीर स्वस्थ रहता है, सहनशक्ति बढ़ती है और शारीरिक क्षमता विकसित होती है। साथ ही, खेल टीमवर्क, अनुशासन, नेतृत्व और समय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सिखाते हैं। खेलों के माध्यम से छात्र सफलता और असफलता दोनों का सामना करना सीखते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। अस्तित्व-2026 में 79 कॉलेजों की 193 टीमों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, टग ऑफ वॉर, शतरंज, कबड्डी और आर्म रेसलिंग जैसे खेल शामिल हैं, जो इस खेल महोत्सव के मुख्य आकर्षण हैं।

संविधान बदलने की बात कहने वाले संगठनों को फंडिंग कर रही मोदी सरकार- कांग्रेस

लोकतंत्र की शान , संवाददाता जीशान अली

नई दिल्लीः कांग्रेस ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांप्रदायिक संगठन 'सनातन संस्था' के उस कार्यक्रम को 63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने और देश के संविधान को खत्म करने की बात कही गई। कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में पार्टी प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने कहा कि 2014 के बाद से देश में कुत्सित विचारधारा वाले संगठन फल-फूल रहे हैं, जो संविधान को दरकिनार कर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से सांप्रदायिक संगठन सनातन संस्था द्वारा दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव' के लिए मोदी सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 63 लाख रुपये देने पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जैसे भाजपा से जुड़े नेता शामिल हुए। रागिनी नायक ने कहा कि इस महोत्सव में मुसलमानों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण, उन्हें देश से भगाने, संविधान को बदलने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई। उन्होंने याद दिलाया कि सनातन संस्था वही संगठन है, जिसकी जांच कर्नाटक पुलिस गौरी लंकेश और एम.एम. कलबुर्गी की हत्या के मामलों में कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठनों ने सनातन शब्द का सबसे ज्यादा अपमान और दुरुपयोग किया है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस ने हमेशा से भारत के संविधान का विरोध किया है। यह कोई संयोग नहीं, भाजपा का प्रयोग है, जिसमें वह संविधान के खिलाफ काम करने वाले संगठनों को पैसा दे रही है। ऐसे संगठन जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को छोड़ दो। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के सांप्रदायिक और भड़काऊ बयानों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वे फ्रिंज एलिमेंट नहीं, बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे नेता हैं। उन्होंने कहा कि जब हिमंता सरमा को वीडियो में मुसलमानों को गोली मारते दिखाया जाता है, तो वह गोली मुसलमानों पर नहीं, संविधान पर चलती है। ऐसी ही नफरत की गोली ने महात्मा गांधी का सीना छलनी किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ऐसे नेताओं को संरक्षण मिलता है।

चीनी रोबोट कुत्ते को अपना आविष्कार बताने के बाद गलगोटिया परिवार को एआई शिखर सम्मेलन से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी

लोकतंत्र की शान, सुनील नेगी

भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धूमधाम से उद्घाटन किए गए एआई शिखर सम्मेलन में सैकड़ों स्टार्टअप कंपनियों ने भाग लिया, लेकिन यह शिखर सम्मेलन उस समय हंसी का पात्र बन गया जब विश्वविद्यालय 'गलगोटिया' ने एक चीनी रोबोट को अपना बताकर पेश किया। हमारे मंत्रियों ने इसकी प्रशंसा की और इस अनूठे रोबोट के आविष्कार और नवाचार में गलगोटिया विश्वविद्यालय के योगदान का समर्थन और संरक्षण किया, जबकि यह रोबोट ऑनलाइन 2800 डॉलर में बिक रहा है। यह चौंकाने वाली बात है कि एक निजी विश्वविद्यालय इतनी प्रामाणिकता से एक चीनी रोबोट को सार्वजनिक रूप से अपना आविष्कार बता रहा है, और जब यह सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैल गया तो चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका खंडन किया, साथ ही कई फेसबुक उपयोगकर्ताओं ने भी। इस प्रकार, एआई शिखर सम्मेलन का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां देशवासियों को झूठ और बयानबाजी से गुमराह और गलत जानकारी दी जा रही है। गलगोटिया विश्वविद्यालय की उत्साही वक्ता सुश्री नेहा द्वारा एआई शिखर सम्मेलन में इस चीनी रोबोट को अपना आविष्कार बताने और यह दावा करने के बाद कि गलगोटिया ने विभिन्न आविष्कारों और नवाचारों पर 350 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, सबूतों के साथ खंडन करने वाला पहला सोशल मीडिया उपयोगकर्ता था... श्री शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखाः "गलगोटिया विश्वविद्यालय ने फिर वही किया। 2800 डॉलर के व्यावसायिक रूप से उपलब्ध रोबोट को एक वैकल्पिक सफलता के रूप में प्रदर्शित किया। 350 रुपये के अनुसंधान एवं विकास का कोई सबूत नहीं है। इस तरह विश्वसनीयता धूमिल होती है। भारत को विश्व मंच पर शर्मिंदा करना बंद करो।" इस आलोचनात्मक ट्वीट के बाद चाइनीज पल्स ने भी अपना खंडन जारी करते हुए गलगोटिया विश्वविद्यालय के रोबोट को ओरियन बताकर और उसे अपना आविष्कार बताते हुए खंडन किया। चाइनीज पल्स ने लिखाः अभी-अभी खबर मिली हैः दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में एक भारतीय विश्वविद्यालय ने चीनी रोबोट यूनिट्री गो2 को अपना आविष्कार बताकर पेश किया। कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इसका खुलकर खंडन किया और विरोध जताया। उन्होंने लिखाः भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय, एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया है - भारतीय डेटा बिक्री के लिए रखा गया है, चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एआई शिखर सम्मेलन की आलोचना करते हुए लिखाः एआई के मामले में मोदी सरकार ने भारत को वैश्विक स्तर पर हंसी का पात्र बना दिया है। चल रहे एआई शिखर सम्मेलन में चीनी रोबोटों को हमारे अपने रोबोट के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह भारत के लिए वाकई शर्मनाक है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी कc मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इसी तरह का झूठ फैला रहc हैं और भारतीय शिखर सम्मेलन में चीन के रोबोटों का प्रचार कर रहc हैं, कांग्रेस ने कहा। गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा खड़ा किया गया यह विवाद और मीडिया द्वारा उन पर जमकर हमला करने और एआई शिखर सम्मेलन का मजाक उड़ाने के बाद, गलगोटिया विश्वविद्यालय को मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन 2026 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विवाद खड़ा करने वाली प्रोफेसर अब बचाव करते हुए कह रही हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने चीनी रोबोट कुत्ते के विवाद पर माफी मांगी है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एआई शिखर सम्मेलन में उसके स्टॉल पर मौजूद एक प्रतिनिधि ने कैमरे के सामने गलत बयान दिए, क्योंकि उसे मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं था, जबकि जानकारी का अभाव था।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026ः 'राजस्थान AI पवेलियन' में प्रदेश ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित गवर्नेंस मॉडल किया प्रस्तुत

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट 2026 में 'राजस्थान AI पवेलियन' आकर्षण का केन्द्र बना है। राजस्थान पवेलियन में राज्य की डेटा-संचालित प्रशासनिक संरचना एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित गवर्नेंस मॉडल को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने बुधवार को 'राजस्थान AI पवेलियन' का दौरा किया और विभिन्न बैठकें कर हितधारकों के साथ विचार—विमर्श किया। साथ ही उन्होंने पवेलियन में स्टार्टअप संचालकों और युवाओं से वार्ता कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार देश का एआई हब बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में आगामी बजट में दो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। राज्य के एआई नवाचारों के बारे में बताते हुए श्री हिमांशु गुप्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार ने संपर्क पोर्टल पर आने वाली नागरिकों की फोन कॉल्स की समाधान प्रक्रिया को भी एआई से जोड़ा है। अब लगभग दस प्रतिशत कॉल्स एआई बॉट के माध्यम से रजिस्टर की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस पवेलियन में लगभग 20 स्टॉल्स के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे नवाचारों को बखूबी दिखाया जा रहा है। एनवीडिया, गूगल इंडिया, सबमर और हेक्सागन एबी के साथ सहयोग पर हुई चर्चा शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सूरपुर और आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता ने इस अवसर पर एनवीडिया, गूगल इंडिया, सबमर और हेक्सागन एबी के अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं। एनवीडिया के साथ एआई कम्प्यूट रेडीनेस, हाई-परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग, रिसर्च और स्टार्टअप विकास पर चर्चा हुई, जिससे राजस्थान को सोवरेन एआई हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। गूगल इंडिया से डिजिटल डेवलपर इकोनॉमी, एंड्रॉयड एआई स्किलिंग और पब्लिक सर्विस इनोवेशन पर वार्ता हुई। सबमर के साथ एआई-रेडी सस्टेनेबल डेटा-सेंटर, लिक्विड कूलिंग और ब्रह्मगुप्त सेंटर से जुड़े स्किलिंग पर फोकस रहा।हेक्सागन एबी से जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्विन्स और एआई एनालिटिक्स का उपयोग पब्लिक सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग तथा जीआईएस-आधारित शासन में करने पर विचार-विमर्श हुआ।ये बैठकें राजस्थान को एआई-सक्षम शासन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम और वैश्विक सहयोग में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सभी हितधारकों ने पार्टनरशिप, पायलट प्रोजेक्ट्स और दीर्घकालिक सहयोग की मंशा जताई।

कार्यालय नगर पंचायत सिरसी जनपद-सम्भल

पत्रांक संख्या- 1280 / न0प0-सिरसी/2025-26 दिनांकः- 18-2-2026

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त ठेकेदारों / फर्मों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के पत्रांक-514/एल.बी.सी./15वाँ वि.आ./ टाइड/अनटाइड ग्रान्ट/02%/ बैठक कार्यवृत्त /2025-26 दिनांक 13 फरवरी, 2026 को स्वीकृति उपरान्त 15वाँ वित्त आयोग (Tied/Untied Grant) व 02 प्रति. अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क' के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नगर में वेस्ट टू वंडर पार्क, ओवर हेण्ड टैंक की सफाई, खड़ंजा निर्माण, कुएं का सौन्दर्यकरण, स्कूल का गेट एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स इत्यादि कार्य कराया जाना है। उक्त कार्य की निविदा की दिनांक 19.02.2026 की प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 11.03.2026 की अपरान्ह 5:00 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय सिरसी में विक्री की जायेगी। सीलबन्द निविदा कार्यालय नगर पंचायत सिरसी में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 12.03.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक आमंत्रित की जायेगी। उक्त निविदाएँ दिनांक 13.03.2026 पूर्वान्ह 11:00 बजे अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिरसी के समक्ष खोली जायेगी। निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्बन्धित ठेकेदार उपस्थित रह सकते है। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सिरसी, सम्भल।

अध्यक्ष
नगर पंचायत सिरसी, सम्भल ।

संक्षिप्त समाचार

सोना उगाने वाले किसानों को समृद्ध कर रही योगी सरकार

लोकतंत्र की शान : गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिट्टी से सोना उगाने वाले अन्नदाता किसानों को प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में हिस्सेदार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने किसानों की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के लिए 'कम लागत-अधिक उत्पादन' की नीति को केंद्र में रखा है, जिसमें नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न जनपदों में किसानों की उल्लेखनीय उपलब्धियां सरकार के इन्हीं प्रयासों की सार्थकता साबित कर रही हैं। राज्य सरकार के बजटीय प्रावधानों और योजनाओं से न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही, बल्कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे में भी जबरदस्त सुधार हो रहा है। कृषि क्षेत्र का उन्नयन और अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि, योगी सरकार के पहले कार्यकाल से प्राथमिकता रही है। बजट में साल दर साल सरकार ने कृषि क्षेत्र के बजटीय प्रावधानों में बढ़ोतरी कर यह जताया भी है।

वाराणसीः सरकारी योजनाओं से किसान भी उत्साहित-पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सरकार ने 2026 -27 के बजट में 20 प्रतिशत अधिक का प्रावधान करते हुए कृषि योजनाओं के लिए 10.888 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। वाराणसी की बात करें तो यहां 94,188 हेक्टेयर में खेती होती है। यहां किसानों की संख्या 3,05,823 है। वाराणसी में 2025 -26 में 558.067 हज़ार मीट्रिक टन खाद्यान्न और 29.354 हज़ार मीट्रिक टन तिलहन का लक्ष्य था। काशी पर सदैव मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। मान्यता है कि यहां कोई भूखा नहीं सोता। यहां की मिट्टी सोना उगलती रहे, इसके लिए बजट में सरकार ने भरपूर इंतजाम भी किया है। प्राकृतिक खेती हो या निर्बाध बिजली आपूर्ति, पशुधन समेत सरकार ने सभी का ध्यान रखा है। सरकार ने बजट में ग्राम्य विकास को 25,500 करोड़ दिए हैं। सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे बिजली की समस्या से राहत मिली है।

ईदगाह, चामुंडा मंदिर मार्ग की जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए ज्ञापन सौंपा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुरः बुधवार को समाजसेवी एवं युवा नेता समीर खान ने नगर के ईदगाह चामुंडा मार्ग को जोड़ने वाली जर्जर सड़क की शीघ्र मरम्मत किए जाने को लेकर एक ज्ञापन पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी के नाम संबोधित करते हुए उनकी अनुपस्थिति में पालिका कार्यालय में दिया, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि नगर के मोहल्ला लाल मस्जिद के निकट बाबू कुरैशी के मकान से चामुंडा मंदिर एवं ईदगाह को जाने वाली सड़क की इन दिनों खसता हालत है, सड़क पर जगह-जगह गड्ढे कीचड़ एवं जल भराव होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वही ज्ञापन में हवाला दिया गया कि रमजान प्रारंभ हो गए हैं तथा ईद व नवरात्रि का त्यौहार भी आने वाला है जिसके चलते इस मार्ग पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों का रोजाना आना-जाना लगा रहेगा वर्तमान में भी इस रोड से सैकड़ो वाहन व सैकड़ो की संख्या में लोग प्रतिदिन गुजर रहे हैं जिनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पत्र के माध्यम से अधिशासी अधिकारी से निवेदन करते हुए कहा गया कि इस जर्जर सड़क की शीघ्र अति शीघ्र मरम्मत कराकर जल निकासी व बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था कराकर राहगीरों तथा नागरिकों को परेशानी से बचाया जाए और दोनों ही समुदाय के त्योहार के दृष्टिगत इस सड़क का दुरुस्त होना जनहित में आवश्यक है। इस मौके पर समाजसेवी युवा नेता समीर खान एवं मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद आरिफ, महेश, बबलू, सतवीर, भोले चौधरी, फरजान कुरेशी, मोहम्मद लइक, मुन्ने इदरीसी, दानियल सैफी जाकिर अल्वी, इमरान भरे कुरैशी आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे

आज बाधित रहेंगी जलापूर्ति

लोक तंत्र की शान : बाँदा। शहर के कटरा जोन अंतर्गत अन्तर्गत आईजीएल द्वारा गैस पाइप लाइन लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य के दौरान जिला कारागार के पास बने ओएचटी को भरने वाली 450 एमएम व्यास की पेयजल पाइप लाइन को रात्रि में क्षतिग्रस्त कर दी गयी है। जिसके कारण जरैली कोठी, बाकरगंज, न्यू मार्केट, क्योटरा क्रासिंग, नोनिया मोहाल, कंचनपुरवा, पीली कोठी, अर्दली बाजार, बलखण्डी नाका आदि मोहल्लों की जलापूर्ति गुरूवार को बाधित रहेगी। जनमानष से अनुरोध है कि पानी का अपव्यय न करें, घरों में स्टोर करके रख लें। आवश्यकता पड़ने पर टैंकर की मांग के लिए जल संस्थान के टैंकर इन्चार्ज शैलेन्द्र कुमार मो. नं. 7398252944, अवर अभियन्ता (जल) अभिलेश कुमार मो. नं. 9415515338, अवर अभियन्ता (जल) मयंक कुमार मो. नं. 9219939616 पर वार्ता कर प्राप्त कर सकते हैं।

ट्रेन से कटकर युवक की मौत

लोक तंत्र की शान : बाँदा। शहर कोतवाली क्षेत्र के जरैली कोठी मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय राजा अनुरागी पुत्री राजेंद्र कुमार अनुरागी मंगलवार की शाम बिना बताए घर से निकल गया और रात को क्योटरा रेलवे क्रासिग के पास ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। उसका शरीर दो भागो में बट गया था। वहां से गुजर रहे राहगीरो ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। तलाशी के दौरान मिले मोबाइल से घरवालों को सूचना दी गई। सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतक के मामा राजकमल ने बताया कि राजा अपने दोस्तो के साथ तिंदवारा स्थित सीट और रोल नबंर कमरा नबंर देखने गया था। रात को वह बिना बताए घर से निकल आया। मां नीतू ने खाना खाने के लिए फोन किया तो राजा ने कहा कि वह कुछ देर में घर आता है। इसके बाद फिर उसका मोबाइल रिसीव नही हुआ। उधर, मृतक के फुफेरे भाई देवानंद ने बताया कि उसका परिवार की एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजा उस महिला से शादी करना चाहता था। घरवाले शादी करने को तैयार नही थे। इसी से परेशान होकर उसने यह घटना अंजाम दी।

बदलता सिरसी, बढ़ता सिरसीः विकास की नई इबारत

» चेयरमैन कौसर अब्बास के नेतृत्व में रचा गया तरक़्क़ी का स्वर्णिम अध्याय

लोकतंत्र की शान

सिरसी। कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझता कस्बा आज विकास की नई पहचान बनता जा रहा है। सिरसी में इन दिनों जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वह केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेतृत्व और मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है। इस परिवर्तन के केंद्र में हैं ,चेयरमैन कौसर अब्बास जिन्होंने विकास को अपना संकल्प और जनसेवा को अपना धर्म बनाया है। नगर की सड़कों का व्यापक पुनर्निर्माण, जल निकासी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता अभियान को गति, आधुनिक स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण—इन सभी कार्यों ने सिरसी की तस्वीर ही बदल दी है। जहां पहले बरसात में जलभराव और अव्यवस्था आम थी, वहीं अब योजनाबद्ध विकास मॉडल अपनाया गया है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि कौसर अब्बास ने केवल प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि नीति निर्धारण और संसाधनों के समुचित उपयोग में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनका स्पष्ट संदेश रहा है कि विकास किसी एक वर्ग या मोहल्ले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे नगर को समान रूप से लाभ मिलेगा। जनता के बीच उनकी सक्रियता और निरंतर जनसंपर्क ने उन्हें एक जननेता के रूप में स्थापित किया है। हर समस्या पर त्वरित संज्ञान, पारदर्शी कार्यशैली और जवाबदेही की भावना ने प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत किया है। स्थानीय व्यापारियों, युवाओं और बुज़ुर्गों का एकमत कहना है कि "सिरसी ने ऐसा विकास और नेतृत्व पहले कभी नहीं देखा।"

आने वाला समय और भी बेहतर- राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यही गति और संकल्प बना रहा, तो आने वाले समय में सिरसी क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि ज़िला स्तर पर एक आदर्श विकास मॉडल के रूप में उभरेगा। चेयरमैन कौसर अब्बास ने संकेत दिए हैं कि आगामी योजनाओं में और अधिक सड़कों का निर्माण, आधुनिक सामुदायिक केंद्र, बेहतर पेयजल व्यवस्था और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार शामिल है। जनता को विश्वास है कि यह तो बस शुरुआत है—आने वाला समय सिरसी के लिए और भी बेहतरीन, और भी व्यापक विकास लेकर आएगा।

हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के पहले दिन आसान पेपर देखकर खिल उठे छात्राओं के चेहरे

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को नगर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं शांतिपूर्ण रूप से प्रारंभ हो गई पहले दिन हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ हुई छात्राओं को तलाशी के बाद एंट्री मिली वहीं पहले दिन पेपर देकर निकली छात्राओं ने बताया कि पेपर आसान था और वह अच्छी तरह से परीक्षा दे पाई, वही परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, पुलिस प्रशासन एवं स्कूल प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरो से सभी परीक्षा कक्षाओं की निगरानी की जा रही थी, पहली पाली सुबह 8:30 बजे प्रारंभ हुई जो 11:45 तक चली उसके बाद दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से प्रारंभ हुई जो 5:15 तक चली, परीक्षा देने आई छात्राओं के चेहरे पर एक तरफ खुशी झलक रही थी दूसरी तरफ परीक्षा देने का प्रेशर भी नजर आ रहा था वही सभी परीक्षा केंद्र का एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने निरीक्षण किया साथ ही फ्लाइंग स्क्वायड ने भी जगह-जगह चेकिंग की

जनविश्वास की मिसालः हज़रत नगर गढ़ी के थाना प्रभारी सुधीर पवार की कार्यशैली बनी प्रेरणा

लोक तंत्र की शान

संभल/सिरसी हज़रत नगर गढ़ी कर्तव्यनिष्ठा, सजगता और मानवीय व्यवहार इन मजबूत स्तंभों पर अपनी पहचान बनाने वाले सुधीर पवार थाना प्रभारी हज़रत नगर गढ़ी, आज क्षेत्र में ईमानदार और बे-मिसाल पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के दिलों में विश्वास और अपनापन पैदा करने वाली है। सुधीर पवार क्षेत्र के लोगों से बड़े ही प्यार-मोहब्बत और आत्मीयता के साथ मिलते हैं। वे हर व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उसकी फरियाद का समय पर निस्तारण कराते हैं। यही वजह है कि थाना क्षेत्र के लोग भी उनसे विशेष प्रेम और सम्मान रखते हैं। "थाना दिवस" के दौरान वे विशेष रूप से आमजन की शिकायतें सुनकर संबंधित मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हैं। उनकी प्राथमिकता रहती है कि किसी भी नागरिक को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और पारदर्शी तरीके से न्याय मिले। ईमानदारी, सादगी और शराफत उनकी पहचान है। सख्ती के साथ संवेदनशीलता का संतुलन बनाए रखना उनकी खासियत है। अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में उनकी भूमिका बेहद सराहनीय रही है। कुल मिलाकर, सुधीर पवार एक ऐसे इमानदार, शरीफ और बे-मिसाल पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिनकी कार्यशैली यह साबित करती है कि यदि प्रशासन जिम्मेदार और जवाबदेह हो, तो जनता का विश्वास अपने आप मजबूत हो जाता है। उनका व्यक्तित्व और सेवा भाव निश्चित ही समाज के लिए प्रेरणा

स्किल हब' बनेगा उत्तर प्रदेश, 'कौशल कनेक्ट सेल' से युवाओं को सीधे मिलेगा रोजगार

लोक तंत्र की शान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब प्रदेश में निवेश करने वाले बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराने के लिए 'कौशल कनेक्ट सेल' का गठन किया गया है। प्रदेश में आने वाले बड़े निवेश को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों को समय पर स्किल्ड मैनपावर मिल सके। इसी उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए 'कौशल कनेक्ट सेल' बनाई गई है।

स्पीडअप-पीएमयू देगा प्रशिक्षण को रफ्तार- प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मिशन में प्रशिक्षण और सेवायोजन (रोजगार) की प्रक्रिया को गति देने के लिए स्पीडअप-पीएमयू को आबद्ध किया गया है। यह पीएमयू अब 'कौशल कनेक्ट सेल' के माध्यम से निवेशकों के साथ रियल-टाइम समन्वय स्थापित करेगा।

डेटाबेस से लेकर सीधे प्लेसमेंट तक जिम्मेदारी- 'कौशल कनेक्ट सेल' केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं होगी, बल्कि इसके कार्य जमीन पर बदलाव लाएंगे। रियल-टाइम ट्रैकिंग कर इन्वेस्ट यूपी के साथ दैनिक समन्वय कर निर्गत प्रोजेक्ट्स की स्थिति को अपडेट रखना यह सेल का मुख्य कार्य होगा। इसके साथ ही किस जिले में कितना निवेश आ रहा है और वहां किस सेक्टर (जैसे ऑटोमोबाइल, आईटी, टेक्सटाइल आदि) में कितने युवाओं की जरूरत है, इसका डेटाबेस तैयार करना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। निवेशकों के एचआर विभाग से लगातार संपर्क में रहना और ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबंधित उद्योगों की जरूरत के अनुसार रोजगार सुनिश्चित करना भी सेल का काम होगा।

35 सेक्टर्स और 1300 जॉब रोल्स में ट्रेनिंग- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा लगभग 35 सेक्टर्स और 1300 से अधिक जॉब रोल्स में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 'कौशल कनेक्ट सेल' के सक्रिय होने से अब ट्रेनिंग और इंडस्ट्री की मांग के बीच का अंतर खत्म होगा और यूपी के युवाओं को उनके जिले में ही बड़े उद्योगों में नौकरी मिल सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 'कौशल कनेक्ट सेल' की स्थापना न केवल प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को 'स्किल हब' के बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

उझारी क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर भाकियू ने प्रदर्शन कर थाने का किया घेराव

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/सैद नंगलीः बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (बी आर अंबेडकर) के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ो की संख्या में ग्रामीणों ने नगर पंचायत उझारी और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के जल्द खुलासे को लेकर थाने का घेराव किया, प्रदर्शनकारी लोगों ने बताया कि उझारी क्षेत्र में हाल ही में तीन /चार बड़ी चोरियां हुई है जिसमें 12 फरवरी को हुई चोरी की घटना का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है जिससे किसानों और ग्रामीणों में असंतोष है, ग्रामीण बड़ी संख्या में पहले हसनपुर स्थित संगठन कार्यालय पहुंचे इसके बाद थाने के घेराव का निर्णय लिया गया, घेराव की सूचना मिलने पर हसनपुर एसडीएम,CO तथा थाना इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि सभी चोरी की घटनाओं जल्द खुलासा किया जाएगा साथ ही बताया कि क्षेत्र में पुलिस गस्त बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध स्थान पर पुलिस बल तनाव किया जाएगा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा वही यूनियन के पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन में समय पर ठोस कार्रवाई नहीं की और चोरों को गिरफ्तार नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन बी आर अंबेडकर अमरोहा कलेक्ट पर बड़ा प्रदर्शन करेगी, फिलहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना घेराव समाप्त कर दिया गया। इस मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे।

फूलपुर बिझलपुर के जंगल में विद्युत विभाग की मिली भगत से हो रही विद्युत चोरी

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बता ते चलें कि लगभग एक महा पूर्व तहसील क्षेत्र के गांव फूलपुर बिझलपुर में 40 विद्युत खंभों पर से विद्युत तार चोरी कर लिया गया था जिसमें अभी तक कोई भी चोर गिरफ्तार नहीं हो पाया है नहीं किसी प्रकार का कोई चोरी से संबंधित किलू मिल पाया है, वहीं जहां एक और 40 खंभों पर से विद्युत तार चोरी हो गए थे वहीं अब विद्युत विभाग की मिली भगत के चलते फूलपुर बिझलपुर के जंगल में बाग में चोरी से विद्युत सप्लाई हो रही है, तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से टिपलर पर विद्युत चोरी करने वालों ने एक ट्रांसफार्मर रखकर पास से गुजर रही उच्च शक्ति की लाइंन में कटवा डालकर विद्युत चोरी की जा रही है, इस प्रकार की विद्युत चोरी बिना विद्युत विभाग के कर्मचारियों के मिली भगत के नहीं हो सकती वहीं जहां विद्युत विभाग की मिली भगत से यह विद्युत चोरी हो रही है वहीं पूर्व में 40 खंभो पर से चोरी गए विद्युत तारों की चोरी में भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों का ही हाथ हो सकता है ये चोरी विद्युत विभाग को संदेह के घेरे में लता है।

चेयरमैन पति चौधरी मुशीर अली खान भूरे शाह रोड पर पहुंचे, जनसमस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान का दिया आश्वासन

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

सम्भल/सिरसी भूरे शाह रोड पर व्याप्त समस्याओं को लेकर आज जिस तत्परता और संवेदनशीलता के साथ पहल की गई, उसने क्षेत्रवासियों के दिलों में विश्वास और सम्मान को और मजबूत कर दिया। चेयरमैन पति एवं वरिष्ठ समाजसेवी चौधरी मुशीर अली खान स्वयं मौके पर पहुंचे और जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उनके साथ सदस्य इब्राहीम अंसारी और सदस्य वकील अहमद भी मौजूद रहे। क्षेत्र के लोगों ने सड़क की जर्जर हालत, जलभराव, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं खुलकर रखीं। चौधरी मुशीर अली खान ने हर व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों से शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक भूरे शाह रोड की हर समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।" मौके पर उपस्थित नागरिकों ने उनकी इस सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि वे हमेशा जनता के बीच रहकर काम करने वाले जनसेवक हैं। भूरे शाह रोड पर आज की यह पहल जनसेवा, जवाबदेही और नेतृत्व क्षमता की मजबूत मिसाल बनकर सामने आई।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां बनेंगी 'सुनीता विलियम्स'

» बालिकाओं को मिल रहा ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का अवसर

» बागपत के गांव तक मुख्यमंत्री योगी ने पहुंचाई हाईटेक एस्ट्रोनॉमी लैब, 45 प्रकार के प्रयोग कर अंतरिक्ष के बारे में समझ रहे बच्चे

लोकतंत्र की शान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को नई उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां भी अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकियां सीख रहीं हैं। बागपत जनपद के छपरौली ब्लॉक में स्थापित अत्याधुनिक एस्ट्रोनॉमी लैब से ग्रामीण छात्राओं के सपनों को उड़ान मिलेगी। ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में बनाई गई इस हाईटेक खगोलशास्त्र प्रयोगशाला के माध्यम से छपरौली ब्लॉक की लगभग 100 बालिकाओं को आधुनिक विज्ञान को समझने का अवसर मिल रहा है। प्रयोगशाला में 45 प्रकार के प्रयोगों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्राएं अंतरिक्ष से जुड़े जटिल सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से समझ रहीं हैं। योगी सरकार के इस प्रयास से अब ग्रामीण पृष्ठभूमि की छात्राएं भी टेलिस्कोप संचालित करने से लेकर नाइट-स्काई ऑब्जर्वेशन तक की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं।

आकाशीय पिंडों की स्थिति, गति और संरचना को डिजिटल माध्यम से समझ रहीं हैं बेटियां- सीएम योगी की इस दूरदर्शी पहल से विज्ञान शिक्षा को नई गति मिल रही है। ब्लॉक संसाधन केंद्र छपरौली में स्थापित एस्ट्रोनॉमी लैब को हाईटेक टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है। बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ छात्राओं को एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे वे आकाशीय पिंडों की स्थिति, गति और संरचना को डिजिटल माध्यम से समझ रहीं हैं। इस तरह का व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में बेहद सहायक होगा।

टेलिस्कोप से चंद्रमा देख बढ़ रहा आत्मविश्वास- इस पहल की सबसे खास बात यह है कि अब छात्राएं स्वयं टेलिस्कोप के माध्यम से चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर रही हैं। जब एक बालिका अपने हाथों से टेलिस्कोप चलाकर चंद्रमा देखती है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास और जिज्ञासा दोनों का विकास होता है।

अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े करियर के बारे में गंभीरता से समझ रहीं बालिकाएं- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय छपरौली की सभी छात्राएं इस लैब में नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रही हैं। नाइट-स्काई प्रेक्षण जैसी गतिविधियां उनके लिए रोमांचक अनुभव साबित हो रही हैं। शिक्षकों का कहना है कि इससे बालिकाओं की विज्ञान के प्रति रुचि तेजी से बढ़ी है और वे अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े करियर के बारे में गंभीरता से सोचने लगी हैं।

एआई-संचालित स्मार्ट क्लास से मिल रही आधुनिक शिक्षा- जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि बागपत में शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले के 25 सरकारी विद्यालयों में एआई-संचालित स्मार्ट क्लास शुरू की गई हैं। इनके माध्यम से बच्चों को इंटरैक्टिव और तकनीक आधारित शिक्षा मिल रही है, जिससे सीखने की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन, मैट्रिक की होम साइंस, 12वीं में फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा

पटना। सीबीएसई की 10वीं-12वीं की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। सीबीएसई की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सभी विषयों की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। CBSE के निर्देशानुसार, छात्रों को कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। ट्रैफिक जाम, रूट डायवर्जन या अन्य कारणों से देरी की संभावना को देखते हुए छात्रों को घर से कम से कम एक घंटा पहले निकलने की सलाह दी गई है। इस साल भारत के साथ-साथ 26 विदेशी देशों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 8000 सेंटर हैं। जहां 46 लाख से अधिक छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पहले दिन 10वीं के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस की परीक्षा होगी, जबकि 12वीं के छात्रों के लिए फिजिकल एजुकेशन का पेपर आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि छात्रों को सुबह 10:00 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना अनिवार्य होगा। 10:00 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्नपत्र सुबह 10:15 बजे बांटे जाएंगे, जबकि 10:30 बजे से छात्र उत्तर लिख सकते है। परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा।

'ईशान किशन की हाइट क्या है, गर्लफ्रेंड कौन', गूगल पर पाकिस्तान में 3 दिन से यही सर्चिंग

पटना। टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे, जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। इस मुकाबले की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी खूब हुई। खासकर ईशान किशन की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की गई। इतना ही नहीं जब ईशान बैटिंग कर रहे थे, उस दौरान से लेकर अब तक पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा उन्हें सर्च किया जा रहा है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक, मैच के दौरान और उसके बाद 'ईशान किशन की उम्र', 'बैकग्राउंड', 'हाइट', 'गर्लफ्रेंड/वाइफ, 'फैमिली' और 'रिलीजन' जैसे कीवर्ड्स तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। यहां तक ईशान किशन की संपत्ति कितनी है और 'उनकी नेटवर्थ क्या है' जैसे सवालों के जवाब भी जमकर खोजे गए। सोशल मीडिया पर उनकी बल्लेबाजी को लेकर कई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। पाकिस्तान के यूजर्स ने ईशान किशन की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "सवा 5 फीट का लड़का पूरी टीम पर भारी पड़ गया।"

पटना वीमेंस कॉलेज में 16 मार्च को स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन, 14 मार्च को चुनाव प्रचार

पटना। पटना वीमेंस कॉलेज में 16 मार्च को स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन होगा। पांच पदों के लिए चुनाव का आयोजन होगा। इस इलेक्शन की जिम्मेदारी कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस विभाग को दी गयी है जिसकी नोडल ऑफिसर डॉ विनिता प्रियदर्शी हैं। चुनाव के कैंपेनिंग को लेकर होली के बाद टीचर्स की प्राचार्या के साथ बैठक होगी, जिसमें प्रसार-प्रचार के साथ इलेक्शन के दिन की रूपरेखा तय की जाएगी। 12 मार्च को छात्राओं को इलेक्शन को लेकर ओरिएंटेशन दिया जाएगा। इसमें बीए, बीएससी और वोकेशनल कोर्स की छात्राएं मौजूद रहेंगी। इसके बाद 13 मार्च को छात्राओं का काउंसलिंग, नॉमिनेशन, विड्रॉल होगा। इसी दिन इलेक्शन के लिए विभिन्न पदों के लिए चयनित छात्राओं की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 14 मार्च को चुनाव प्रचार होगा। 15 मार्च को ब्रेक रहेगा। वहीं 16 मार्च को इलेक्शन होगा। इसी दिन परिणाम की घोषणा की जाएगी। पटना वीमेंस कॉलेज में पांच पदों के लिए चुनाव होगा। इसमें प्रीमियर, जनरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और एनवायरमेंट एंड डिसिप्लिन सेक्रेटरी शामिल है। इसके अलावा छात्राएं वाइस प्रीमियर, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट कल्चरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और ज्वाइंट एनवायरमेंट एंड डिसिप्लिन सेक्रेटरी के लिए खड़ी होती हैं। वहीं, इसमें प्रिंसिपल नॉमिनी के तौर पर दो छात्राओं का चयन होता है।

वैशाली में दो रोड एक्सीडेंट, 6 लोग घायल, पीएचसी में डॉक्टर नहीं मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया

हाजीपुर। बुधवार सुबह वैशाली के राघोपुर फतेहपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में दो अलग-अलग सड़क हादसों में घायल करीब आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण मरीजों का उपचार नहीं हो सका, जिससे आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं, जिससे मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। उन्होंने मांग की कि अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घायलों के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर न होने के कारण मरीजों का घंटों तक इलाज नहीं हो सका। पहली घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के खुदगाश गांव में बुधवार सुबह हुई। यहां एक बाइक और साइकिल की टक्कर में बाइक सवार और साइकिल सवार दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत पीएचसी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उनका इलाज घंटों तक नहीं हो पाया। घायलों में पहाड़पुर पूर्वी निवासी रुदल चौधरी के पुत्र कुंदन कुमार और फतेहपुर निवासी एक साइकिल सवार शामिल हैं। कुंदन कुमार जिम से लौटते समय दुर्घटना का शिकार हुए। दूसरी घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत के कन्हैया चौक के पास हुई। यहां एक बाइक और सीएनजी टेंपो की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर राहगीर एवं आसपास के लोग जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर फतेहपुर लाया गया। हालांकि डॉक्टर नहीं रहने के कारण घंटों तक घायलों का इलाज नहीं हो सका। घायल बाइक सवार फतेहपुर निवासी सोनू कुमार शर्मा और विक्रम कुमार शर्मा जबकि CNG टेंपो सवार मनीष कुमार एवं मेघन कुमार बताया गया है। घायल सोनू कुमार शर्मा ने बताया कि बाइक से कन्हैया चौक स्थित अपने दुकान जा रहे थे इसी दौरान बाइक और टेंपो की टक्कर हो गई। वहीं घायल मनीष कुमार और मेघन कुमार सीएनजी टेंपो से कच्ची दरगाह रुस्तमपुर जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते मंगलवार की रात्रि डॉक्टर मनीष कुमार झा की ड्यूटी थी, बुधवार की सुबह करीब 6:00 बिना किसी डॉक्टर के आए मनीष कुमार अस्पताल से निकल गए। बुधवार की सुबह से अस्पताल में डॉक्टर निभा कुमारी की ड्यूटी थी। निभा कुमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां डॉक्टर के आने और जाने का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। हमेशा यहां डॉक्टर गायब रहते हैं। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी एवं हेल्थ मैनेजर भी नहीं आते हैं। भगवान भरोसे यह अस्पताल चल रहा है।

बम से उड़ाने की धमकी मामले में टीम गठित हुई

रोज सुबह के वक्त कोर्ट में सर्च ऑपरेशन, अब धमकी का भी असर नहीं

एजेंसी, पटना

पटना सिविल कोर्ट को लगातार बम से उड़ने की धमकी मिलने के बाद अब पुलिस रोज सुबह के वक्त कोर्ट में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुबह 7:00 से लेकर कोर्ट खुलने से पहले तक पूरे परिसर को सेनीटाइज कर दिया जा रहा है। यह कदम एहतियातन बराबर मिल रही धमकी के बाद उठाया गया है। धमकी भरे मेल को लेकर ATS ने अपने बयान पर केस रजिस्टर्ड किया था। इसकी भी जांच अब शुरू हो गई है। डीएसपी रैंक के पदाधिकारी इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठितः टाउन डीएसपी राजेश रंजन ने बताया कि, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। इसमें थाने से भी तकनीकी सहायता ली जा रही है। दो तीन बार फिर से धमकी आई है, लेकिन पुलिस अलर्ट है। इस तरह की धमकी से कोर्ट का काम जो प्रभावित हो रहा था, वो अब नहीं होने वाला है।

कोर्ट परिसर की सुरक्षा हर तरह से चाक चौबंधः टाउन डीएसपी के मुताबिक, पटना सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा हर तरह से चाक चौबंध कर दी गई है। सुबह के वक्त पिरबहोर थाने की पुलिस की मौजूदगी में पूरे परिसर की तलाशी लेने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात कर्मियों को हैंड ओवर किया जा रहा है। उन्हें प्रॉपर जांच के लिए सख्त हिदायत दी गई है। पटना कोर्ट में अब तक 7 बार काम प्रभावित अब तक सात बार से अधिक इस तरीके के धमकी वाले मेल आ चुके हैं। इससे पहले जब भी मेल आता था, कोर्ट को बंद कर दिया जाता था और फिर तलाशी ली जाती थी। वकील भी इस बात को लेकर काफी नाराज चल रहे थे। सातवीं बार जब धमकी मिली थी तो वकीलों ने मुख्य गेट पर बैठकर प्रदर्शन भी किया था। हालांकि, SSP के आश्वासन के बाद मान गए थे।

फायरिंग में घायल होटल करोबारी की स्थिति नाजुक

एजेंसी, पटना

- स्टेटमेंट पर दूसरी केस दर्ज, 15 में से एक आरोपी पिस्टल के साथ धराया

पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मोहिनी मोड़ के पास मंगलवार रात गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें भूतनाथ इलाके का रहने वाला होटल कारोबारी विकास घायल हो गया था। विकास की बयान पर बुद्धा कॉलोनी थाने में दूसरी फिर रजिस्टर्ड हुई है। 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस की ओर से जो फिर हुई है, उसमें 15 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। गोलीबारी की इस घटना से वरीय अधिकारी सकते में हैं। सूत्रों की माने तो DIU की टीम ने ASP कृष्ण मुरारी प्रसाद के साथ मीटिंग की है। बताया जा रहा है कि वह दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में सभी लड़ गए और एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। विकास का फिलहाल मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। एसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि, 'एक आरोपी पिस्टल के साथ पकड़ा गया है, जिसका नाम पुटूश है। इसके पास से जो पिस्टल मिली है, वह अवैध है। फिलहाल, उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें से कुछ लोगों का अपराधी इतिहास भी पाया गया है। शास्त्री नगर और कृष्णापुरी थाने में अपराधिक मामले दर्ज हैं।' जिन दो गुटों में लड़ाई हुई है, वह लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। कई बार आपस में बोरिंग रोड में दबदबा कायम करने के लिए कहा-सुनी भी हो चुकी है। मंगलवार के दिन भी सभी ने एक साथ कृष्णापुरी इलाके में बर्थडे पार्टी मनाई थी। इस दौरान जमकर शराब भी पिया। इसके बाद सभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और लड़ते झगड़ते मोहिनी मोड़ के पास आकर फायरिंग शुरू कर दी।

दानापुर सगुना मोड़ पर चलती थार में आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

एजेंसी, पटना

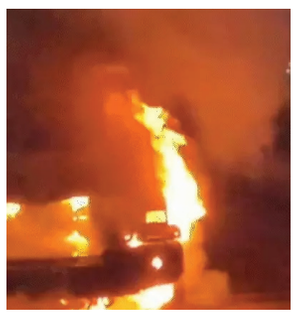

पटना के दानापुर के सगुना मोड़ पर सगुना पुलिस चौकी के पास मंगलवार देर रात एक चलती महिंद्रा थार गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी लपटों से घिर गई। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चलती थार से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ और कुछ ही देर में आग की लपटें निकलने लगीं। आग को विकराल रूप लेते देख गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक तुरंत बाहर निकल आया और अपनी जान बचाई।

दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पायाः आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दो दमकल गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों की तत्परता से आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों और दुकानों को नुकसान होने से बचा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अग्निशमन अधिकारी विजय शंकर यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट से थार गाड़ी में आग लगी थी। गाड़ी मालिक हर्ष राज ने भी इंजन में अचानक आग लगने की बात कही।

बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा : 7 फीट ऊंची दीवार फांदकर सेंटर में घुसा, एंट्री नहीं मिलने पर छात्रा ने किया सुसाइड

एजेंसी, पटना

- राज्यभर के 1699 परीक्षा केंद्रों पर करीब 15 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल

बिहार मैट्रिक (10वीं) परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दोनों पालियों में गणित (मैथ्स) की परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। मुंगेर के मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर गेट बंद हो जाने के बाद 7 फिट ऊंची दीवार फांदकर छात्र सेंटर में घुस गया। राज्यभर के 1699 परीक्षा केंद्रों पर करीब 15 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भागलपुर में एंट्री के दौरान एक दिव्यांग परीक्षार्थी को पुलिसकर्मियों ने गोद में उठाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। इधर, मसौढ़ी के खरजमा गांव की छात्रा कोमल कुमारी ने परीक्षा छूट जाने के बाद ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली।

मंगलवार को बरनी स्थित केंद्र पर उसकी परीक्षा थी। बताया जा रहा है कि वह परीक्षा देने के लिए सोमवार को ही अपने रिश्तेदार के गांव महाराजचक गई थी।

परीक्षा केंद्र बरनी में था, जो करीब 6 किलोमीटर दूर था। सुबह 9 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन वह 9:10 बजे केंद्र पहुंची। नियमानुसार गेट बंद कर दिया गया था। काफी कोशिशों के बावजूद जब प्रवेश नहीं मिला तो वह लौट आई। कुछ देर बाद वह नदौल पहुंची और ट्रेन में सवार हो गई। तरेगना और मसौढ़ी कोर्ट स्टेशन के बीच महाराजचक गांव के पास चलती ट्रेन से कूद गई। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस साल परीक्षा में करीब 15.12 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। पहली पाली में लगभग 7.58 लाख और दूसरी में करीब 7.54 लाख परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा केंद्र पर जूता और मोजा पहनकर नहीं आएं। सुरक्षा जांच को आसान बनाने के लिए यह नियम लागू किया गया है।

दरभंगा में जल-जीवन-हरियाली अभियान से हरसिंगपुर में लौटी खुशहाली, चेक डैम से खत्म हुआ जल संकट

एजेंसी, पटना

- लाखों की लागत से निर्मित इस चेक डैम ने गांव के जल संकट को समाप्त करने के साथ कृषि और पशुपालन को नई दिशा दी

बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड अंतर्गत लगभग चार हजार की आबादी वाले हरसिंगपुर गांव में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बने चेक डैम ने ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। लाखों रुपये की लागत से निर्मित इस चेक डैम ने गांव के जल संकट को समाप्त करने के साथ-साथ कृषि और पशुपालन को नई दिशा दी है। कुछ वर्ष पहले तक हरसिंगपुर गांव में वर्षा जल संचयन की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। बरसात के दौरान पानी तेजी से बहकर नदियों और नालों में चला जाता था, जिससे जल संरक्षण संभव नहीं हो पाता था। गर्मियों में भू-जल स्तर अत्यंत नीचे चला जाता था, जिसके कारण कुएं, चापाकल और अन्य जलस्रोत सूख जाते थे।

इस स्थिति में गांव की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी और किसान केवल एक फसल ही उगा पाते थे। सिंचाई के अभाव में उत्पादन कम होता था, जिससे किसानों की आय घट गई थी। साथ ही पशुपालन और घरेलू उपयोग के लिए भी पानी की भारी कमी बनी रहती थी। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण गांव के युवाओं को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता था। गांव की इस गंभीर समस्या को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने जल संचयन के लिए चेक डैम निर्माण का निर्णय लिया। इसके तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत 9 लाख 84 हजार रुपये की लागत से चेक डैम का निर्माण कराया गया। चेक डैम बनने से अब वर्षा जल का संचयन संभव हो गया है और इससे गांव के किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। लगभग 250 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा करीब 500 पशुधन के लिए भी पानी की उपलब्धता आसान हो गई है।

चेक डैम बनने के बाद गांव में खेती की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब किसान सब्जी, तिलहन और दलहन जैसी फसलों की खेती भी करने लगे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हरसिंगपुर के किसान शंकर यादव ने बताया कि चेक डैम बनने से गांव में पानी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है और खेती तथा पशुपालन में काफी सुधार हुआ है। वहीं किसान उमेश यादव ने कहा कि यह योजना जल संरक्षण और ग्रामीण विकास की दिशा में अत्यंत सफल साबित हुई है।

चेक डैम बनने से गांव में हरियाली बढ़ी है और पर्यावरणीय संतुलन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। इस परियोजना से अब तक 670 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी जलस्रोत बनने से गांव में खुशहाली लौटी है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बना यह चेक डैम गांव के लिए विकास का नया द्वार साबित हुआ है और भविष्य में भी यह जल प्रबंधन और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

बिहार विधानसभा में उठा प्रवासी मजदूरों के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने का मुद्दा

एजेंसी, पटना

बिहार विधानसभा में असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों से जुड़ा मुद्दा उठाया गया। सदस्य अख्तरूल इमाम ने दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में प्रवासी मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग की।

सदन में उन्होंने कहा कि बिहार के लगभग 70 प्रतिशत परिवार किसी न किसी रूप में प्रवासी मजदूरों पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि किसी प्रवासी मजदूर की राज्य के बाहर या विदेश में स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को पार्थिव शरीर लाने में भारी आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि स्वाभाविक मृत्यु के मामलों में भी सरकार पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ले।

इस पर जवाब देते हुए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि वर्तमान प्रावधानों के तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का दायित्व सरकार उठाती है।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में, चाहे वह राज्य के भीतर हो या बाहर, पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने का कोई अलग से प्रावधान फिलहाल लागू नहीं है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विभागीय स्तर पर विचार किया जाएगा। चर्चा के दौरान सदस्य कुमार सर्वजीत ने यह भी प्रश्न उठाया कि अब तक कितने मजदूरों को इस योजना का लाभ मिला है। इसके उत्तर में मंत्री संजय सिंह टाइगर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक इस मद में 2,58,547 रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जा रही है।

रामचक बैरिया में कचरा प्रोसेसिंग की कैमरे से होगी मॉनिटरिंग

एजेंसी, पटना

- पटना में आईसीसीसी कैमरे से जुड़ी मशीनें, मॉनसून से पहले लेगेसी वेस्ट के डिस्पोजल का टारगेट

पटना में कचरे के प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए रामचक बैरिया में काम काफी तेजी से चल रहा है। आज नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने समीक्षा की। उन्होंने मॉनसून से पहले रामचक बैरिया में लेगेसी वेस्ट के निष्पादन का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने 31 मई 2026 तक कूड़े के साइंटिफिक प्रोसेसिंग और डिस्पोजल का निर्देश दिया है। रामचक बैरिया में कार्यरत सभी एजेंसियों को उनके-उनके स्थल चिन्हित कर आवंटित कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे तुरंत मैन फोर्स बढ़ाए।

5 सदस्यीय निगरानी समिति का गठनः पूरे कार्य की प्रभावी निगरानी के लिए 5 सदस्यीय "लेगेसी वेस्ट कमेटी" का गठन किया गया है। कूड़े के साइंटिफिक प्रोसेसिंग के लिए विंड्रोज़ पद्धति अपनाई जा रही है, जो पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप है। इसके साथ ही सभी एजेंसियों को लेगेसी वेस्ट के प्रोसेसिंग और RDF (Refuse Derived Fuel) मटेरियल के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मौके पर कार्यरत तीन एजेंसियों में से दो एजेंसियों का काम असंतोषजनक पाए जाने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

रामचक बैरिया के मशीन ICCC कैमरे से जुड़ेः यहां स्थापित सभी मशीनों के नजदीक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) तथा पटना नगर निगम के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, जिससे कामों की 24×7 मॉनिटरिंग की जाएगी। मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए फायर हाइड्रेंट और बोरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जलापूर्ति की बैठक में 13 लोगों से मांगा गया स्पष्टीकरणः इसके अलावा आज नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जलापूर्ति की बैठक भी आयोजित हुई। इस समीक्षा बैठक में योजना के सभी अधिकारियों ने कार्य प्रगति का डिटेल प्रस्तुत किया गया जो असंतोषजनक पाया गया। वार्ड नंबर- 21,16, 27, 36, 18, 42 और 24 में चल रही जलापूर्ति, पटना अंतर्गत राज्य योजना से संबंधित योजनाओं के 13 संवेदक और संबंधित अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए बनेगा फ्लाइंग स्क्वाड टीमः आज नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा में नमामि गंगे परियोजना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना, जलापूर्ति योजनाएं, विद्युत शवदाह गृह निर्माण सहित अन्य आधारभूत संरचना विकास कार्यों की डिटेल समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अब योजनाओं की निगरानी पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय में बैठे-बैठे ही वीडियो कॉल के जरिए परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे। उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन कर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया।

संक्षिप्त समाचार

बम्हनगवां के शासकीय स्कूल में हुई दुखद दुर्घटना में मृत छात्र के निधन पर विधायक संजय पाठक ने जताया दुख ,दिया तत्कालिक आर्थिक सहयोग

लोकतंत्र की शान : हसन रशीद लोकतंत्र किस हसन रसीद जिला विरोधी जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश: विजयराघवगढ़ के कैमोर थाना क्षेत्र के ग्राम बम्हनगवां स्थित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला के पुराने भवन की जर्जर बाउंड्रीवॉल गिरने से कक्षा पांचवीं में अध्ययनरत 10 वर्षीय छात्र रपटा मोहल्ला निवासी राजकुमार बर्मन पिता स्वर्गीय महेंद्र बर्मन के निधन का समाचार मिलने पर विधानसभा की कार्यवाही के भोपाल गए विधायक संजय पाठक ने सबसे पहले अधिकारियों से दुर्घटना के कारणों की जानकारी लेते हुए घटना पर दुख व्यक्त कियाउन्होंने कहा कि यह घटना हृदय को झकझोर देने वाली है। बर्मन परिवार पर आए आघात को सहन करने लिए अपनी तरफ से तत्कालिक आर्थिक सहयोग प्रदान करने एवं शासकीय नियमों के अनुसार मदद एवं इस तरह के जर्जर भवन एवं परिसरों की सघन जांच करने जिससे आगामी समय में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस संबंध में अधिकारगणों से संवाद कर कार्यवाही के कहा।

हिसार : आज का युग पूर्णतः डेटा-आधारित निर्णयों का युग : प्रो. नरसी राम बिश्नोई

लोकतंत्र की शान : हिसार। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस (एचएसबी) में डेटावर्स क्लब की ओर से बीबीए विद्यार्थियों के लिए 'एसक्यूएल' पर चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दो दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को डेटाबेस प्रबंधन और डेटा विश्लेषण की मूलभूत एवं व्यावहारिक समझ प्रदान करना है, जिससे वे उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बुधवार को कहा कि आज का युग पूर्णतः डेटा-आधारित निर्णयों का युग है, जहां तकनीकी साक्षरता के बिना व्यावसायिक सफलता की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एसक्यूएल जैसी तकनीकें विद्यार्थियों को डेटा को समझने, व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने की ठोस क्षमता प्रदान करती हैं। एसक्यूएल जैसी भाषा विद्यार्थियों को डेटा के साथ आत्मविश्वास के साथ कार्य करने में सक्षम बनाती है। एचएसबी के निदेशक प्रो. संजीव कुमार ने कहा कि डेटावर्स क्लब द्वारा आयोजित यह कार्यशाला अकादमिक शिक्षा को व्यावहारिक कौशलों से जोड़ने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब विद्यार्थी स्वयं प्रशिक्षण की भूमिका में आते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बनती है। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ाती हैं, बल्कि नेतृत्व, टीमवर्क और जिम्मेदारी की भावना को भी सुदृढ़ करती हैं। निदेशक ने भविष्य में भी ऐसे कौशल-आधारित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की बात कही।

देसंविवि की एक और कीर्तिमान, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

लोकतंत्र की शान : हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने एक और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि अपने नाम की है। विश्वविद्यालय के एमएससी (मानव चेतना एवं योग विज्ञान) प्रथम वर्ष के छात्र अभिषेक कुमार ने अपनी असाधारण साधना, एकाग्रता और शारीरिक क्षमता के बल पर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है। विवि के योग विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 2026 को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड की ओर से एक ऑनलाइन स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में देसंविवि के छात्र अभिषेक कुमार ने 31 मिनट में 331 सूर्य नमस्कार पूर्ण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, अनुशासन और नियमित अभ्यास का परिणाम है। इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में सूर्य नमस्कार करना शारीरिक सहनशक्ति, श्वास-नियंत्रण और मानसिक संतुलन का अद्वितीय उदाहरण है। विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक योग प्रशिक्षण पद्धति ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिषेक कुमार ने पूर्व में भी योग क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने द्विपाद विपरीत दंडासन जैसी जटिल मुद्रा में 11 मिनट 05 सेकंड तक स्थिर रहकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था। इसके लिए उन्होंने योग के शारीरिक अभ्यास के साथ ही आत्मबल और साधना की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास किया। इस उपलब्धि का प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात अभिषेक कुमार ने विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या से भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रतिकुलपति ने इसे विश्वविद्यालय की समृद्ध योग परंपरा के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि यह सफलता युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अभिषेक ने अपनी सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय के पारिवारिक वातावरण और सकारात्मक सोच को दिया। योग विभाग सहित समस्त विवि परिवार ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

समस्याएं हल नहीं होने पर भड़के जल संस्थान के श्रमिक

लोकतंत्र की शान : पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड जल संस्थान एवं उत्तराखंड जल निगम में ठेका प्रथा के तहत कार्यरत कार्मिकों ने तीन सूत्रीय मांगों का हल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक कर्मचारी संघ के मंत्री ने तीन सूत्रीय मांगों के समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ ने विभागीय अधिकारियों पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा कि पिछले लंबे समय से समस्याओं के हल की मांग की जा रही है लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिससे उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को जिलाधिकारी से मिलने आए संघ के पदाधिकारयो ने कहा कि 10 वर्षों से अधिक समय से सेवारत कार्मिकों को विभागीय नियुक्ति दी जाए। कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए। संघ ने श्रीनगर के श्रीकोट स्थित शक्ति विहार में बिना नोटिस हटाए गए 36 कार्मिकों की पुनः बहाली की मांग उठाई।

सीधी में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ग्राहक पंचायत का ज्ञापन

लोकतंत्र की शान

सीधी। नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पहले निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली एवं पुस्तकों व यूनिफॉर्म की खरीद को लेकर अभिभावकों पर डाले जा रहे अनैतिक दबाव के विरोध में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिला सीधी (म.प्र.) ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में विद्यालयीन शिक्षा का नया सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में कुछ निजी विद्यालय अभिभावकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल रहे हैं तथा उन्हें विशेष निजी दुकानों से ही पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।मंगलवार 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे सीधी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने एसडीएम गोपद बनास को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महाकौशल प्रांत पदाधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष श्री नीरज मिश्रा, उपाध्यक्ष प्रभु शरण सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपते समय सचिव श्री विष्णु पनाडिया, श्री राकेश चतुर्वेदी, श्री पुनीत कुमार त्रिपाठी, श्री मुनीष शुक्ला, श्री राम सिंह एवं अन्य सदस्यों ने प्रशासन को अवगत कराया कि यदि निजी विद्यालयों की इस प्रकार की अनियमितताओं पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो संगठन जनआंदोलन के लिए बाध्य होगा। ग्राहक पंचायत ने माननीय मुख्यमंत्री से विषय की गंभीरता को समझते हुए प्रदेशभर में निजी विद्यालयों की फीस संरचना एवं खरीद संबंधी व्यवस्थाओं की जांच कर कठोर कदम उठाने की मांग की है।

खनिज विभाग ने हरचोका खदान से अनाधकृत रेत परिवहन करते 5 हाइवा पर की कार्यवाही

लोकतंत्र की शान

सीधी। रेत के अवैध उत्खनन परिवहन और लगाम लगाने कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित की गई है। दरमियानी रात खनिज विभाग ने 5 हाइवा ट्रक पर कार्यवाही करते हुए क्रमशः ग्राम-पथरौला, तहसील-मड़वास में 3 वाहन क्रमशः बिना नंबर के वाहन हाइवा चेसिस क्रमांक MAT448181G3H19269, MP53ZG6670 एवं MP53HA2379 को खनिज रेत के अनाधिकृत परिवहन करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार जब्त कर सुरक्षार्थ पुलिस चौकी पथरौला खड़ा कराया गया है। वही ग्राम-खाम्ह, तहसील-गोपद बनास में 2 वाहन क्रमशः हाइवा क्रमांक MP17ZG3011 एवं MP53HA2337 को खनिज रेत के अनाधिकृत परिवहन करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार जब्त कर सुरक्षार्थ थाना कोतवाली सीधी में खड़ा कराया गया है। सभी 5 (पांचो) वाहनों में हरचोका (छत्तीसगढ़) से रेत लोड होना पाया गया है। उक्त वाहनों पर मप्र खनिज (अवैध उत्खनन एवं परिवहन) की धारा 3 के तहत कार्यवाही की गई है।

सोनीपतःऊना के मैड़ी मेले में मालवाहक वाहनों में न जाएं श्रद्धालु

लोकतंत्र की शान

सोनीपत। सोनीपत उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित मैड़ी में बाबा बड़भाग सिंह होली मेले का आयोजन 24 फरवरी से छह मार्च तक किया जा रहा है। इस मेले में जाने वाले श्रद्धालु मालवाहक वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक व ट्रालों आदि में न जाएं क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के जिले में प्रवेश को लेकर रोक लगाई है। उपायुक्त ने बुधवार को बताया कि ऊना जिला के उपायुक्त जतिन लाल ने पत्र लिखकर यह जानकारी दी है कि हरियाणा से काफी संख्या में श्रद्धालु ट्रकों, ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों तथा ट्रालों में सवार होकर मैड़ी स्थित बाबा बड़भाग सिंह होली मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हें जिला ऊना की सीमा से आगे मालवाहक वाहनों में नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती अंतर्राज्यीय बैरियर पर की जाएगी। ऊना जिला के उपायुक्त द्वारा सभी श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए बसों में ही यात्रा करें और मालवाहक वाहनों में आने से बचें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश रोडवेज द्वारा भी मेले में जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है।

नेशनल लोक अदालत के संबंध में सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंको के अधिकारीगण के साथ मीटिंग का आयोजन

लोकतंत्र की शान

सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में श्री यतीन्द्र कुमार गुरू विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत की अध्यक्षता में 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बुधवार दिनांक 18 फरवरी 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी में सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंको के अधिकारीगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विभाग लोक अदालत हेतु अपने लंबित प्रकरणों की अद्यतन सूची तैयार कर समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी को उपलब्ध कराए, साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें सामंजस्य की संभावना है, उन्हे प्राथमिकता के आधार पर लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाए। उक्त मीटिंग के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोनी ने बताया कि लोक अदालत न केवल न्यायालयों का भार कम करने का माध्यम है, बल्कि यह आम नागरिकों को कम समय, कम खर्च एवं आपसी समझौते से सरल एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी मंच है, जहाँ आपसी सहमति के माध्यम से वर्षों से लंबित प्रकरणों का समाधान संभव है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ''विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं शीघ्र समाधान'' है और इसके लिए सभी विभागों एवं राष्ट्रीयकृत बैंको के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे लोक अदालत योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर समय रहते सूचीबद्ध करें, जिससे अधिक से अधिक मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। नेशनल लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा। उक्त बैठक में श्री यतीन्द्र कुमार गुरू विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत, श्री राकेश कुमार सोनी प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी, श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा तृतीय जिला न्यायाधीश सीधी, श्री मुकेश कुमार शिवहरे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लीड बैंक सीधी एवं अन्य संबंधित संस्थानों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस–बैंकों की बैठक

» जागरूकता बढ़ाने एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर हुआ मंथन

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन में बुधवार को कंट्रोल रूम सभागार, कटनी में जिले के समस्त सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के प्रबंधकों/अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर जागरूकता को बढ़ावा देना तथा बैंक एवं एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस और बैंकों के बीच मजबूत एवं सतत समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड, संदिग्ध लेन-देन, एटीएम एवं बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा साइबर फ्रॉड की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे ग्राहकों को साइबर अपराधों से बचाव हेतु निरंतर जागरूक करें तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव आम नागरिकों की मेहनत की कमाई पर पड़ता है। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस और बैंकों के बीच सशक्त समन्वय अत्यंत आवश्यक है। जिला पुलिस जनधन की सुरक्षा एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठा रही है और भविष्य में भी बैंकों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी बैंक कर्मचारियों से अपील की गई कि साइबर अपराधों से निपटने में पुलिस को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना/सक्रियता तथा जिले में घटित साइबर अपराधों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी थानों एवं सायबर सेल द्वारा सूचना मांगी जाए, तो बैंक अधिकारी शीघ्र एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे जालसाजों का विवरण समय पर एकत्र कर बरामदगी और कार्रवाई को आसान बनाया जा सके। बैठक के अंत में पुलिस एवं बैंक अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की गई। इस अवसर पर बैंक एवं एटीएम सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारी, पुलिस साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह सहित साइबर सेल के पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

अजमेर सहित जिले के कई कस्बों में मेघ गर्जन के साथ हुई तेज बारिश

लोकतंत्र की शान

अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में बुधवार सुबह मौसम में अचानक बदलाव दर्ज किया गया। किशनगढ़ उपखंड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चने के आकार के ओले गिरे। बाजेड़ा बालाजी और बांदरसिंदरी सहित कई इलाकों में खेतों में ओलों की परत देखी गई। इस समय क्षेत्र में गेहूं, चना और सरसों की फसल पकाव की अवस्था में है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जिले में मौसम बदला है। मंगलवार देर रात मेघगर्जन के साथ मसूदा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की सूचना है। एक मकान की छत की पट्टियां क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है। हालांकि किसी प्रकार के जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। अजमेर शहर में सुबह करीब नौ बजे तेज बौछारों के साथ बारिश हुई। घने बादलों के कारण दृश्यता प्रभावित रही। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और शीतलहर जैसे हालात बने। किशनगढ़ क्षेत्र में ओलावृष्टि की सूचना प्रशासन को दी गई है। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को भी मौसम बदलाव से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूर्व में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। किसानों ने फसलों की सुरक्षा के प्रयास किए थे, लेकिन कई स्थानों पर नुकसान की आशंका बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने 20 फरवरी से फिर से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है।

सीधी में पुजारी हत्याकांड पर गरमाई सियासत,जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह का सरकार,प्रशासन पर तीखा हमला अतिक्रमण, ट्रांसफर पोस्टिंग और माफिया पर उठाए सवाल

लोकतंत्र की शान

सीधी। एमपी के सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र में हुए पुजारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक माहौल तेज हो गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद उन्होंने शोक संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पुजारी की हत्या बेहद निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।वही ज्ञान सिंह ने मामले से जुड़े अतिक्रमण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उनका कहना था कि यदि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, तो सरकार को उसे नियमानुसार मुक्त कराना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक कार्रवाई में पारदर्शिता की कमी है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। जहा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि आजकल ट्रांसफर–पोस्टिंग "पैसे के नंबर" पर हो रही हैं, जिसके कारण अधिकारी पदस्थापना के बाद कथित रूप से पैसा वसूलने में जुट जाते हैं। उन्होंने इस प्रथा पर तत्काल रोक लगाने और जवाबदेही तय करने की मांग की। वही इसके अलावा, ज्ञान सिंह ने जिले में सक्रिय माफिया गतिविधियों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेत, मुरुम, मिट्टी और अवैध शराब से जुड़े तस्करों की सूची पुलिस के पास होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं, आम नागरिकों पर छोटी–छोटी बातों में कार्रवाई होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे "सरकार की मनसा" बताया। वही ज्ञान सिंह ने स्पष्ट किया कि वे इस पूरे प्रकरण को विधानसभा स्तर तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मामले को नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के समक्ष रखकर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे और सदन में संबंधित प्रश्न भी उठाएंगे। जहा घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय नागरिकों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के बीच अब सबकी नजरें प्रशासनिक जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। वही शोक संवेदना व्यक्त करने के दौरान सीधी जिले के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह के अलावा कांग्रेस के युवा चेहरा ज्ञानेन्द्र अग्निहोत्री जिला पंचायत सदस्य शेषमणि प्रसाद पनिका आनंद सिंह शेरगांव ब्लॉक अध्यक्ष विमल जयसवाल सहित कई कांग्रेसी क्षेत्रीय नेता उपस्थि रहे परिवार को सान्तावना दिये।

बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी और कर्ज में डूबेगा मध्य प्रदेश :- ज्ञान

लोकतंत्र की शान

सीधी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने इसे जनता से विश्वासघात करने वाला, दिशाहीन और जनविरोधी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो बड़े वादे किए थे, वे ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी केवल घोषणाओं तक सीमित हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण में किसानों, महिलाओं और आम उपभोक्ताओं से किए गए प्रमुख वादों का उल्लेख तक नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट चुकी है। ज्ञान सिंह ने कहा कि चुनाव के समय किसानों से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल तथा गेहूं का 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया था, किंतु बजट में इसके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती लागत, महंगे बीज, खाद और डीजल की कीमतों से जूझ रहे किसानों को राहत देने के बजाय सरकार ने उन्हें निराश किया है। इसी प्रकार लाड़ली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 3000 रुपये देने तथा 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा भी बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण और महंगाई राहत के नाम पर किए गए ये वादे अब केवल चुनावी जुमले साबित हो रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारी मात्रा में कर्ज लिया गया है और बजट का बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्ज के ब्याज और मूलधन की अदायगी में खर्च हो रहा है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है कि विकास और जनकल्याण की योजनाओं पर खर्च करने के बजाय सरकार को कर्ज चुकाने में बड़ी राशि लगानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश पर बढ़ता कर्ज आर्थिक कुप्रबंधन का परिणाम है और इसका बोझ अंततः प्रदेश की जनता पर ही डाला जा रहा है। ज्ञान सिंह ने कहा कि यह विडंबना है कि मध्य प्रदेश का वार्षिक बजट उस कुल कर्ज से भी कम है, जो प्रदेश पर चढ़ चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के समुचित प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में विकास कार्य और अधिक प्रभावित होंगे तथा जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि पिछले बजट में की गई घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत क्यों नहीं की गई। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन की ठोस योजना का अभाव, महंगाई पर नियंत्रण के उपायों की कमी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अपर्याप्त प्रावधान यह दर्शाते हैं कि यह बजट आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल है। ज्ञान सिंह ने कहा कि यह बजट विकास का नहीं, बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी और प्रचार का दस्तावेज है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार की वादा-खिलाफी तथा आर्थिक कुप्रबंधन के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। मध्य प्रदेश की जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है और समय आने पर इसका उत्तर अवश्य देगी।

संक्षिप्त समाचार

मेयर ममदानी बोले- अमीरों पर टैक्स लगाना जरूरी, न्यूयॉर्क की आर्थिक हालत ठीक नहीं

नई दिल्ली। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य के नेता अमीर लोगों और कॉर्पोरेशन्स पर ज्यादा टैक्स लगाने की मंजूरी नहीं देते हैं, तो न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क शहर में प्रॉपर्टी टैक्स कमाई का बड़ा जरिया है। टैक्स बढ़ने से सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा, जिससे वह अपने बजट घाटे को कम कर सकती है। हालांकि इससे महंगाई बढ़ जाएगी। ममदानी ने कहा कि शहर के सामने मुश्किल विकल्प हैं। घाटा भरने के लिए उन्होंने दो रास्ते बताए। पहला रास्ता यह है कि अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया जाए। दूसरा रास्ता यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाए और रिजर्व फंड से पैसा निकाला जाए। उन्होंने कहा कि यह विकल्प ज्यादा कठिन और नुकसानदेह है। ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क शहर राज्य को ज्यादा सेवाएं देता है, लेकिन बदले में उसे उतना पैसा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अगर राज्य के कानून बनाने वाले कदम नहीं उठाते, तो शहर के पास दूसरा रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रॉपर्टी टैक्स में करीब 9.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पिछले 20 साल से ज्यादा समय में पहली बड़ी बढ़ोतरी होगी।

अमेरिकी सांसद बोले- कुत्तों-मुसलमानों में से एक को चुनना आसान

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन के एक सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने मंगलवार को X पर लिखा कि अगर कुत्तों और मुसलमानों में से एक को चुनना पड़े तो यह मुश्किल फैसला नहीं है। दरअसल, रैंडी फाइन ने यह टिप्पणी न्यूयॉर्क में एक फिलिस्तीनी-अमेरिकी एक्टिविस्ट नरदीन किसवानी की पोस्ट के जवाब में की थी। किसवानी ने लिखा था कि कुत्ते अपवित्र हैं। ऐसे समय में जब न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, कुत्तों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इन्हें बैन करना चाहिए। इस पर फाइन ने कहा कि दुनिया में 57 ऐसे देश हैं, जहां शरिया कानून लागू है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वहीं चले जाइए। अमेरिका 58वां मुस्लिम देश नहीं बनेगा। बाद में किसवानी ने कहा कि वह बस मजाक कर रही थीं। यह न्यूयॉर्क में सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की गंदगी को लेकर चल रही बहस से जुड़ा था। ऐसा उन लोगों के लिए कहा गया था, जो राजनीति में मुस्लिमों के बढ़ते प्रभाव को खतरा मानते हैं। किसवानी ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने फार्म पर एक कुत्ते को गोली मारने की बात कही थी। किसवानी ने लिखा, 'क्रिस्टी नोएम ने अपने ही कुत्ते को गोली मारने की बात कही और ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम कह दे कि शहर पालतू जानवरों के लिए सही जगह नहीं है तो उसे मौत की धमकियां मिलने लगती हैं।' किसवानी ने फाइन पर फिलिस्तीनियों और मुसलमानों को अमानवीय दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से आ रही मुस्लिम विरोधी भाषा पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती।

नेपाल में आयोग ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और भविष्यवाणी पर रोक लगाई

काठमांडू। नेपाल के निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया हाउस और सर्वे एजेंसियों के चुनाव-पूर्व सर्वेक्षणों और चुनावी परिणाम की भविष्यवाणी के प्रकाशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग के कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने आज सुबह बयान जारी कर कहा कि आयोग के तरफ से सभी मीडिया और सर्वे एजेंसियों को किसी भी प्रकार के चुनावी सर्वेक्षण और चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी के प्रकाशन और प्रसारण पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा कि मतदान से पहले जीत–हार के अनुमान और जनमत सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित करने जैसी गतिविधियां चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। भंडारी ने व्यक्तियों और मीडिया संस्थानों से यह भी अपील की कि वे सोशल मीडिया पर एआई और अन्य डिजिटल उपकरणों से तैयार भ्रामक सामग्री का निर्माण या प्रसार न करें। चुनाव की निष्पक्षता की रक्षा और मतदाताओं के गुप्त मतदान के अधिकार को साझा संवैधानिक दायित्व बताते हुए भंडारी ने पांच मार्च को निर्धारित चुनाव के सफल आयोजन के लिए सभी से सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया।

एमपी-राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आज से बर्फबारी

भोपाल/शिमला/जयपुर/लखनऊ/देहरादून। उत्तर और मध्य भारत पर अगले 36 घंटों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत 9 राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम में बदलवा आया है। इस वजह से मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी आई है। राज्य के 22 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के 5 जिलों में भी मंगलवार को बारिश हुई। आज सुबह से जयपुर में बारिश-ओलावृष्टि जारी है। 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बुधवार से बर्फबारी-बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बर्फबारी संभव है। इधर उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के राज्यों में दिन का तापमान 30°C तक पहुंचा है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

शादी में डांस करते-करते आया हार्ट अटैक, बड़वानी में मेहंदी की रस्म में दूल्हे के मामा की मौत

बड़वानी। खरगोन में मेहंदी की रस्म के दौरान दूल्हे के मामा को हार्ट अटैक आ गया। वे नाचते-नाचते जमीन पर गिर पड़े। परिजन ने इसे उनका डांस स्टेप ही समझा। कुछ देर तक जब वे नहीं उठे तो रिश्तेदार उनकी तरफ बढ़े। उन्हें निढाल देखकर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। मामला खरगोन के वझरा गांव का है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बड़वानी में पिपलुद गांव के रहने वाले घनश्याम यादव (40) अपने भांजे की शादी में वझरा आए थे। मंगलवार रात को मेहंदी की रस्म थी। इस दौरान घनश्याम अपनी पत्नी के साथ नाच रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य भी जश्न में शामिल थे। घनश्याम यादव पेशे से किसान थे। करीब आठ एकड़ जमीन है। उनके साथ उनकी पत्नी और इकलौता बेटा भोला यादव भी मौजूद थे। भोला 8वीं क्लास में पढ़ता है। वे भांजे अंकित और भांजी रजनी की शादियों में भात लेकर मंगलवार को ही वझरा पहुंचे थे। शाम को मेहंदी के साथ ही संगीत भी रखा गया था।

ममता सरकार बोली- ईडी केंद्र का हथियार, एजेंसी ने कहा- हमें बंगाल में धमकाया

हम तय करेंगे कौन हथियार और किसे धमकाया गया: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली/कोलकाता

पश्चिम बंगाल में I-PAC से जुड़े रेड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) का उन राज्यों में हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जहां विपक्ष की सरकार है। वहीं केंद्रीय एजेंसी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी के हथियार नहीं हैं। बंगाल में ममता सरकार ने हमें धमकाया। दोनों पक्षों के बीच बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है, यह हम तय करेंगे। ED ने I-PAC रेड मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ED का आरोप है कि 8 जनवरी को I-PAC के ऑफिसों पर रेड के दौरान CM ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने उनकी कार्रवाई में रुकावट डाली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 मार्च तक टाल दी है। इससे पहले 3 फरवरी को सुनवाई टाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ED की जांच में बाधा डालना बहुत गंभीर मुद्दा है।

I-PAC रेड मामला : 2,742 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस: I-PAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। यह राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। CBI ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की थी। पूरा मामला 2,742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए I-PAC तक ट्रांसफर हुए। ED ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। 8 जनवरी 2026 को ED ने कोलकाता में I-PAC और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था।

रेड के दौरान फाइलें लेकर चली गईं थी CM ममता: सर्च ऑपरेशन के दौरान, CM ममता बनर्जी अन्य TMC नेताओं के साथ I-PAC ऑफिस पहुंचीं। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। ममता ऑफिस से कई फाइलें लेकर बाहर निकलीं और मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर हद से ज्यादा दखलंदाजी का आरोप लगाया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि I-PAC पार्टी के चुनाव रणनीतिकार के रूप में काम करता है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ED ने गोपनीय चुनाव रणनीति से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए रेड डाली। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। TMC ने ED की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप का खंडन किया। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की।

चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस वायरल बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स भी किया

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी

चीन ने सोमवार को दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखाई। एक कार्यक्रम में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मार्शल आर्ट्स और डांस किया। करीब 25 रोबोट्स बच्चों के साथ तलवार भांजते, बैकलिफ्ट करते और डंडे घुमाते हुए डांस करते दिखाई दिए। खास बात यह रही कि एक भी रोबोट गिरा नहीं। यह प्रदर्शन देख दुनिया हैरान रह गई। कई लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर रोबोट अब नाच सकते हैं और कुंग फू कर सकते हैं, तो वे और क्या कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल अलग था। पिछले साल रोबोट्स सिर्फ रुमाल घुमाते और साधारण हरकतें करते नजर आए थे। लेकिन एक साल में सबकुछ बदल चुका है। चीन दुनिया को खासकर अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वह तकनीक में बहुत आगे निकल चुका है। एशिया में टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी के प्रमुख जॉर्ज स्टीलर ने कहा कि जिस गाला में इन रोबोट्स ने प्रदर्शन किया, वह कई सालों से चीन की तकनीकी ताकत दिखाने का बड़ा मंच रहा है। इसी मंच पर चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम, ड्रोन और रोबोट जैसी नई तकनीकों को दुनिया के सामने पेश करता रहा है।

एक्सपर्ट्स बोले- चीन ने रोबोटिक्स में अमेरिका को पछाड़ा

उन्होंने कहा कि इस गाला की सबसे खास बात यह है कि यहां सरकार की औद्योगिक नीति और टीवी के बड़े शो के बीच सीधा संबंध दिखाई देता है। यानी जिन कंपनियों को इस मंच पर अपने प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिलता है, उन्हें बाद में सरकारी ऑर्डर, निवेशकों की दिलचस्पी और बाजार में आसानी से एंट्री जैसे फायदे मिलते हैं। स्टीलर के मुताबिक सिर्फ एक साल में रोबोट्स की क्षमता में बड़ा बदलाव आया है। अब उनकी चाल-ढाल और मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है।

राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव, इनमें 25 सीटें विपक्ष, एनडीए की 12

एजेंसी, नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास हैं, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल-बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। शरद पवार, रामदास अठावले, कणिमोझी, तिरुचि शिवा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी।

बैलेट पेपर पर खास पेन से होगी वोटिंग: चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट डालते समय केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए तय मानक का वॉयलेट रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल होगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। आयोग ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में EVM और VVPAT को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। आयोग के मुताबिक 5 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 1.20 लाख से ज्यादा लोगों ने डेमो कैंप में हिस्सा लिया। 1.16 लाख से ज्यादा लोगों ने मॉक वोट डाले। 10 फरवरी तक 29 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन मोबाइल डेमो वैन से कवर किए जा चुके हैं।

पटाखा फैक्ट्री में 7 लोग जिंदा जले थे, मालिक-मैनेजर गिरफ्तार, प्लॉट मालिक के घर पहुंची पुलिस

एजेंसी, भिवाड़ी

राजस्थान के भिवाड़ी के अवैध पटाखा फैक्ट्री के मालिक हेमंत कुमार शर्मा और मैनेजर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत भिवाड़ी पुलिस की DST टीम में तैनात हेड कॉन्स्टेबल योगेश कुमार शर्मा का भाई है। 16 फरवरी को भिवाड़ी के खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से पटाखा बनाते समय धमाका हुआ था।

इसमें ठेकेदार सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। भिवाड़ी एएसपी अतुल साहू ने बताया- विस्फोट मामले में तीसरे नामजद आरोपी प्लॉट मालिक राजेंद्र कुमार के गाजियाबाद स्थित घर पर 16 फरवरी की रात पुलिस की टीम पहुंची थी। वहां परिवार वालों ने बताया था कि राजेंद्र को ब्रेन ट्यूमर है। उसका इलाज चल रहा है।

17 फरवरी को राजेंद्र के परिजन खुशखेड़ा थाने पहुंचे थे। उन्होंने लिखित में दिया कि वे राजेंद्र कुमार को लेकर थाने में उपस्थित हो जाएंगे। गुरुवार को राजेंद्र कुमार नहीं आता है तो दोबारा से उसके घर और अन्य संबंधित जगहों पर दबिश देकर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा।

4 आरोपियों में से दो गिरफ्तार, एक की मौत: एएसपी ने बताया-16 जनवरी के हादसे को लेकर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था। इसमें फैक्ट्री मालिक हेमंत कुमार निवासी शाहजहांपुर (खैरथल-तिजारा), मैनेजर अभिनंदन निवासी मोतिहारी (बिहार), प्लॉट मालिक राजेंद्र निवासी गाजियाबाद (UP) और ठेकेदार अजीत निवासी खुशखेड़ा (भिवाड़ी) शामिल थे। हेमंत और अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट है।

एक आरोपी भिवाड़ी डीएसटी के हेड कॉन्स्टेबल का भाई

ठेकेदार अजीत की हादसे में ही मौत हो चुकी है। डीएनए जांच और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

हादसे के बाद एक फैक्ट्री और एक गोदाम सील: जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ था, उसे पुलिस ने उसी दिन (16 फरवरी) को सील कर दिया था। जांच के दौरान 17 फरवरी को घटनास्थल से 500 मीटर के दायरे में एक और अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदाम होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने इन दोनों को भी सील कर दिया था। इनका मालिक भी हेमंत कुमार शर्मा है। इस फैक्ट्री और गोदाम से अवैध पटाखों की बड़ी खेप मिली थीं। फैक्ट्री में पटाखा बनाने वाली बड़ी-बड़ी मशीनें लगी थीं।

अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना, अमेरिका बोला- ईरान शर्तें नहीं मान रहा, हमारे पास दूसरे रास्ते मौजूद

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे हैं। इंडिपेंडेंट फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया है।

यह जानकारी अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनेवा में हुई दूसरी दौर की बातचीत के दौरान सामने आई है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तय की गई शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि बातचीत के कुछ हिस्से सकारात्मक रहे, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। इन बयानों से साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत अभी भी नाजुक दौर में है। ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान अमेरिकी मांगें नहीं मानता, तो अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करेगा।

अमेरिका ने रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट भेजे: अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट की ओर जाते देखे गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि विमान लंबे समय तक ऑपरेशन की तैयारी में हैं। इस बीच, अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि USS जेराल्ड आर. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से रवाना होकर मिड-अटलांटिक में पहुंच चुका है और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अगले चार-पांच दिन में उसके पहुंचने की उम्मीद है।

न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, सुरक्षा कारणों से नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि फोर्ड के साथ तीन गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर, USS माहान, USS बैनब्रिज और USS विन्सटन चर्चिल भी हैं। इससे पहले USS अब्राहम लिंकन और अन्य महत्वपूर्ण अमेरिकी एयर और नेवल एसेट्स भी इस साल की शुरुआत में क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं। इससे अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी और मजबूत हुई है।

बठिंडा में किसानों-पुलिस के बीच पथराव, भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे, कई घायल

एजेंसी, बठिंडा

बठिंडा के जिओंद गांव के पास पुलिस और किसानों के बीच भारी टकराव हो गया। किसानों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।

इस टकराव में पुलिस और किसानों की ओर से कई लोग घायल हुए हैं। जबकि, कुछ को गैस चढ़ गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर किसानों को फौरन सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। SSP ज्योति यादव ने कहा कि स्थिति कंट्रोल करने के लिए पुलिस अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही है।

इससे पहले भारतीय किसान यूनियन (BKU) एकता उगराहां के नेतृत्व में बठिंडा शहर की ओर निकाले गए मार्च को पुलिस ने रोक दिया। किसान बठिंडा में डिप्टी कमिश्नर (DC) के ऑफिस के बाहर धरना देने जा रहे थे। जिसके बाद किसान रामपुराफूल से पहले बठिंडा-चडीगढ़ हाईवे पर अपनी मांगों को लेकर धरना देकर बैठ गए। पुलिस फोर्स किसानों को रोकने के लिए पहुंची, लेकिन किसान नहीं माने।

पटियाला-संगरूर में भी झड़प

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से नेपाल के विदेशमंत्री ने की मुलाकात

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल के विदेशमंत्री बालानंद शर्मा ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से शिष्टाचार मुलाकात की है। शर्मा ने उन्हें बधाई दी और नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की ओर से शुभकामना संदेश सौंपा। संदेश में रहमान की चुनावी जीत की सराहना करते हुए आपसी सम्मान, साझा प्राथमिकताओं और साझेदारी के आधार पर नेपाल–बांग्लादेश संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

ढाका स्थित नेपाली राजदूतावास के तरफ से आज जारी एक बयान में कहा गया है कि नेपाल के विदेशमंत्री शर्मा ने 12 फरवरी को हुए राष्ट्रीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए भी रहमान को बधाई दी और बांग्लादेश में शांतिपूर्ण व सफल लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री रहमान ने शपथ ग्रहण समारोह में शर्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह बांग्लादेश के प्रति नेपाल सरकार और नेपाली जनता की एकजुटता तथा सद्भावना को दर्शाता है। बयान में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराने की जानकारी दी गई है। रहमान ने नेपाल में आगामी पांच मार्च को होने जा रहे संसदीय चुनाव के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नेपाल में भी आम चुनाव के जरिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा।

महाराष्ट्र में मुस्लिमों के 5% आरक्षण का आदेश रद्द

एजेंसी, मुंबई

महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजोल्यूशन (GR) जारी किया। इसके जरिए सरकार ने अपने 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को कैंसिल कर दिया। जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। हालांकि पिछले 10 सालों से यह आदेश इनवैलिड रहा है क्योंकि 2014 में कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया अध्यादेश तय समय (6 हफ्ते) में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका, जिससे यह खुद ही इनवैलिड हो गया था। जुलाई 2014 में कांग्रेस-एनसीपी की गठबंधन की सरकार थी। अक्टूबर 2014 में सरकार बदल गई। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा-शिवसेना सरकार बनी। नई सरकार ने नौकरी वाले मुस्लिम आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया।

2008-2013: सरकार ने मुस्लिम समुदाय पर रिपोर्ट बनाई: कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने से पहले पांच सालों (2008–2013) तक रिसर्च की। सरकार ने सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति पर कई कमेटियां/रिपोर्ट्स बनवाईं। नतीजा यह निकला कि मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्ग पिछड़े हैं, इसलिए आरक्षण की सिफारिश की गई।

जुलाई 2014 : सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का आरक्षण देने का फैसला: कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार में तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मुस्लिमों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसे अध्यादेश/सरकारी आदेश के जरिए लागू करने की कोशिश हुई। यह फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया, इसलिए राजनीतिक विवाद भी हुआ। अगस्त से सितंबर के बीच नियम को लागू करने की शुरुआत हुई। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए 5% कोटा लागू होना शुरू हुआ। नौकरी वाला हिस्सा भी नोटिफिकेशन में था, पर जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाया।

2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी, पास न होने से 10 सालों से इनवैलिड, कोर्ट भी लगा चुकी रोक

अक्टूबर 2014 : फैसले को कोर्ट में चुनौती, बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक: मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। शिक्षा में 5% आरक्षण जारी रखने की अनुमति मिली। वहीं सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि नौकरी वाले आरक्षण के लिए पर्याप्त ठोस डेटा नहीं दिखाया गया। 2015 से 2018 के बीच अदालतों में केस चलता रहा। राज्य सरकार ने अलग मुस्लिम कोटा की जगह OBC/SEBC श्रेणी के अंदर लाभ देने की बात कही। हालांकि अलग 5% मुस्लिम कोटा पर कोई नया मजबूत कानून नहीं आया। नीति लागू नहीं हुई।

भारत की सड़कों पर ट्रैफ़िक कानून बनाम लापरवाही- क्या ट्रैफिक कानून हार रहा है?पैसा, पहुंच,पहचान,दबंगई जीत रही है? -लोकतंत्र,जनसंख्या और ट्रैफिक अनुशासन का गहन विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हालिया आंकड़े सड़क सुरक्षा,पर्यावरण संरक्षण और विधि शासन के लिए गंभीर चुनौती है

» ट्रैफिक अधिनियमों का सख़्ती से क्रियान्वयन नहीं करना यह केवल प्रशासनिक शिथिलता का प्रश्न नहीं,बल्कि शासकीय मानसिकता,तकनीकी ढांचे, राजनीतिक इच्छाशक्ति और नैतिक अनुशासन का भी मुद्दा है -एडवोकेट किशन षणमुख दास भवानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत आज 142.6 करोड़ से अधिक आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।इतनी विशाल जनसंख्या,विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ ,तीव्र शहरीकरण और तेजी से बढ़ते मोटर वाहनों के बीच कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना किसी भी सरकार के लिए असाधारण चुनौती है।भारत में हजारों केंद्रीय और राज्य कानून लागू हैं और अधिकांश क्षेत्रों में उनका पालन संतोषजनक रूप से होता भी है। किंतु सड़क परिवहन और ट्रैफिक कानूनों का क्रियान्वयन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यवस्था और वास्तविकता के बीच गंभीर अंतर दिखाई देता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहता हूं कि जनता पर लागू प्रमुख सड़क परिवहन कानून और नियमः(1)मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019:यह कानून सड़क सुरक्षा बढ़ाने और नियमों के उल्लंघन (जैसे- बिना हेलमेट / सीटबेल्ट,शराब पीकर गाड़ी चलाना) पर भारी जुर्माने के लिए लागू है।(2)केंद्रीय मोटर वाहन नियम,1989:यह वाहन के तकनीकी मानकों (जैसे- प्रदूषण, लाइट,सुरक्षा उपकरण) को निर्धारित करता है।(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002: यह राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने और यातायात के सुचारू संचालन को नियंत्रित करता है।(4) सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007:यह माल परिवहन करने वाले वाहकों के नियमों और दायित्वों से संबंधित है।(5)परिवहन परमिट (धारा 66-70): व्यावसायिक वाहनों के लिए वैध परमिट अनिवार्य है।इन अधिनियमों का सख़्ती से क्रियान्वयन नहीं करना यह केवल प्रशासनिक शिथिलता का प्रश्न नहीं है,बल्कि सामाजिक मानसिकता, तकनीकी ढांचे, राजनीतिक इच्छाशक्ति और नैतिक अनुशासन का भी मुद्दा है।भारत में सड़क सुरक्षा का मूल कानूनी ढांचा मोटर व्हीकलस एक्ट पर आधारित है,जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, इन अधिनियमों का उद्देश्य वाहन पंजीकरण,ड्राइविंग लाइसेंस बीमा,फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना है। 2019 में इस कानून में व्यापक संशोधन किए गए,जुर्मानों को बढ़ाया गया,डिजिटल प्रवर्तन को प्रोत्साहित किया गया और राज्यों को अधिक दायित्व सौंपे गए।इसके बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में पंजीकृत लगभग 40.7 करोड़ वाहनों में से 70 प्रतिशत से अधिक वाहन किसी न किसी वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं। इनमें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र,वैध बीमा,फिटनेस सर्टिफिकेट और समय पर पंजीकरणनवीनीकरण जैसी अनिवार्य शर्तें शामिल हैं। केवल लगभग 8 करोड़ वाहन ही पूर्णतः अनुपालन की श्रेणी में आते हैं,जबकि 30 करोड़ से अधिक वाहन अधूरे दस्तावेजों के साथ सड़कों पर चल रहे हैं।इसके अतिरिक्त 2 करोड़ से अधिक वाहन ऐसे हैं जिनका पंजीकरण पहले ही निरस्त किया जा चुका है,किंतु वे डेटाबेस में दर्ज हैं।यह स्थिति केवल प्रशासनिक आंकड़ों कीसमस्या नहीं है;यह सड़क सुरक्षा,पर्यावरण संरक्षण और विधि शासन के लिए गंभीर चुनौती है।भारत में सबसे बड़ी चिंता दोपहिया वाहनों को लेकर है। गैर- अनुपालन वाले वाहनों में लगभग 23.5 करोड़ दोपहिया वाहन शामिल हैं।हेलमेट का उपयोग न करना,तीन-तीन लोगों का बैठना,नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना,बीमा या फिटनेस न होना,ये दृश्य देश के हर छोटे-बड़े शहर में सामान्य हो चुके हैं। महाराष्ट्र के छोटे शहर गोंदिया से लेकर महानगरों तक ट्रैफिक अनुशासन की कमी स्पष्ट दिखाई देती है।सिग्नल तोड़ना,गलत दिशा में वाहन चलाना मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करना, सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए स्टंट करना,ये सब अब केवल अपवाद नहीं रहे,बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति बनते जा रहे हैं।द्वारका की घटना में मृतक की मां द्वारा कही गई बात,कि यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि मानसिकता का प्रश्न है,भारत की सड़क सुरक्षा बहस का केंद्रीय बिंदु है। सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की होड़,तेज रफ्तार को स्टेटस सिंबल मानना,और कानून को चुनौती देने की प्रवृत्ति एक नई पीढ़ी के भीतर उभरती दिखाई देती है।डिजिटलप्लेटफॉर्म पर खतरनाक स्टंट्स के वायरल होने से युवाओं में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए केवल दंड पर्याप्त नहीं; शिक्षा, जागरूकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी आवश्यक है। साथियों बात अगर हम हाल की घटनाओं ने इस संकट को और भी स्पष्ट कर दिया है इसको समझने की करें तो फरवरी 2026 में दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बाइक सवार युवक को टक्कर मारने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना उस समय हुई जब आरोपी कथित रूप से सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के उद्देश्य से वाहन चला रहा था। मृतक युवक की मां का सार्वजनिक बयान इस घटना को महज दुर्घटना नहीं, बल्कि आपराधिक मानसिकता का परिणाम बताता है।उनका दर्द केवल व्यक्तिगत शोक नहीं था;वह एक ऐसी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह था जहाँ कुछ लोग स्वयं को कानून से ऊपर समझने लगते हैं।इस घटना में आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। भारत में नाबालिगों से संबंधित मामलों का निपटान जुवेंइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) एक्ट के तहत किया जाता है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों के पुनर्वास और सुधार पर बल देना है, न कि दंडात्मक प्रतिशोध पर। किंतु जब अपराध की प्रकृति गंभीर हो, विशेषकर तब जब उसमें जान का नुकसान हुआ हो, तो समाज में न्याय और दया के बीच संतुलन को लेकर व्यापक बहस शुरू हो जाती है।द्वारका प्रकरण में आरोपी को बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई,जिससे पीड़ित परिवार और आम जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं।इससे पहले पुणे में हुई चर्चित पोर्श दुर्घटना ने भी देश को झकझोरा था। वहाँ भी एक नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाने से गंभीर दुर्घटना हुई थी और आरोपों में साक्ष्य मिटाने की बात सामने आई थी। ऐसे मामलों में प्रश्न केवल व्यक्तिगत अपराध का नहीं, बल्कि अभिभावकीय जिम्मेदारी सामाजिक प्रतिष्ठा, धनबल और प्रभाव के दुरुपयोग का भी है। जब परिवार अपने नाबालिग बच्चों को उच्च क्षमता वाले वाहन चलाने की अनुमति देते हैं, तो यह केवल कानूनी उल्लंघन नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी है। साथियों बात अगर हम भारत में प्रतिवर्ष लाखों सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं इसको समझने की करेंतो,इसमें हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें बताती हैं कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सड़क दुर्घटनाएँ मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं। भारत, जिसकी सड़क नेटवर्क लंबाई विश्व में सबसे अधिक में से एक है, सड़क सुरक्षा के मामले में अभी भी विकसित देशों से काफी पीछे है। विकसित देशों में सख्त प्रवर्तन,स्वचालित कैमरा प्रणाली, उच्च दंड और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के कारण अनुपालन दर अधिक है।भारत सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक में वाहन डेटाबेस को साफ करने और चरणबद्ध तरीके से गैर- अनुपालन वाहनों को स्वतः डी-रजिस्टर करने का प्रस्ताव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि तय समयसीमा के भीतर बीमा,फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते,तो ऐसे वाहनों को स्वतः निष्क्रिय करने की व्यवस्था लागू की जा सकती है। यह कदम केवल तकनीकी सुधार नहीं होगा;यह प्रशासनिकइच्छाशक्ति की परीक्षा भी होगा। सड़क सुरक्षा का प्रश्न केवल कानून या पुलिस तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक संस्कृति का प्रश्न भी है। भारत में कई लोग ट्रैफिक जुर्माने को मामूली खर्च या समझौते का अवसर मान लेते हैं। कुछ स्थानों पर ट्रैफिक विभाग को मलाईदार विभाग कहे जाने का कारण भी यही धारणा है कि प्रवर्तन पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है। जब कानून का पालन कराने वाला तंत्र ही विश्वास खो देता है, तो नागरिक अनुशासन भी कमजोर पड़ जाता है। साथियों बात कर हम पर्यावरणीय दृष्टि से इस पूरे मुद्दे को समझने की करें तो भी 30 करोड़ से अधिक गैर- अनुपालन वाले वाहनों की उपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है। बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के वाहन वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं,जो पहले से ही कई भारतीय शहरों में खतरनाक स्तर पर है। प्रदूषण और सड़क सुरक्षा दोनों ही सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े मुद्दे हैं।यदि भारत को 21वीं सदी में एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना है,तो सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुपालन को प्राथमिकता देनी ही होगी।यह भी ध्यान देने योग्य है कि कानूनों की संख्या पर्याप्त है; समस्या क्रियान्वयन की है। पुलिस बल की कमी,न्यायिक लंबित मामले, तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता और राजनीतिक हस्तक्षेप—ये सभी प्रवर्तन को प्रभावित करते हैं। यदि किसी राज्य में ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों का शीघ्र निपटान नहीं होता, तो दंड का निवारक प्रभाव कम हो जाता है। साथियों बात अगर हम समाधान के रूप में कुछ ठोस सुझावों को समझने की करें तो, पहला, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों के लिए कठोर दंड का अनिवार्य प्रावधान और उसका वास्तविक क्रियान्वयन। दूसरा, सभी वाहनों के लिए डिजिटल अनुपालन ट्रैकिंग और गैर-अनुपालन पर स्वचालित जुर्माना। तीसरा, स्कूल स्तर से सड़क सुरक्षा शिक्षा कोअनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल करना। चौथा,सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय कर खतरनाक स्टंट्स के प्रचार पर रोक। पाँचवाँ ट्रैफिक पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र।भारत का लोकतंत्र विशाल और जीवंत है। परंतु लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं; यह कानून के समक्ष समानता और नागरिक जिम्मेदारी का भी नाम है। जब सड़क पर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है, तो वह केवल व्यक्तिगत जोखिम नहीं लेता; वह दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है। द्वारका की घटना में एक मां का आक्रोश हमें याद दिलाता है कि हर दुर्घटना के पीछे एक परिवार का बिखरना छिपा होता है।यदि 70 प्रतिशत वाहन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो यह केवल प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि सामूहिक चेतना का संकट है। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की आकांक्षा के साथ-साथ सामाजिकअनुशासन और विधि-पालन की संस्कृति भी विकसित करनी होगी। सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित कर केंद्र और राज्यों को समन्वित, तकनीक-समर्थित और पारदर्शी ढांचा अपनाना चाहिए। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तरपर इसको समझने की करें तो अनुभव बताते हैं कि सड़क सुरक्षा सुधार के लिए बहु-स्तरीय रणनीति आवश्यक होती है—कानून का कठोर प्रवर्तन, तकनीकी निगरानी, सड़क अवसंरचना में सुधार, वाहन सुरक्षा मानकों का उन्नयन और नागरिक शिक्षा। भारत में भी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, ई-चालान प्रणाली, और एकीकृत वाहन डेटाबेस जैसी पहलों से सुधार संभव है। परंतु जब तक स्थानीय स्तर पर निरंतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक आंकड़ों में सुधार सीमित रहेगा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह लेख किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक व्यापकआह्वान है।सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वह पैदल यात्री हो, साइकिल सवार, बाइक चालक या कार ड्राइवर सुरक्षा का अधिकार रखता है। कानून का सम्मान और अनुशासन का पालन ही उस अधिकार की रक्षा कर सकता है। यदि सरकार प्रस्तावित ढांचे को सख्ती से लागू करे, वाहन डेटाबेस को शुद्ध करे और गैर- अनुपालन पर वास्तविक दंड सुनिश्चित करे,तो भारत सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है। भारत का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था या तकनीकी क्षमता से नहीं तय होगा; वह इस बात से भी तय होगा कि वह अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है। सड़क पर अनुशासन, कानून का निष्पक्ष प्रवर्तन और सामाजिक जिम्मेदारी—ये तीनों मिलकर ही उस सुरक्षित और जिम्मेदार भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसकी कल्पना एक सशक्त लोकतंत्र करता है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

इबादत का पाक महिना है रमजान

लेखक - डॉ. श्रीगोपाल नारसन

इस्लाम धर्म को मानने वाला हर मुस्लमान रमजान का बेसब्री से इन्तजार करता है। रमजान शुरू होते है तो हर रोजेदार की दिनचर्या बदल जाती है। बडे सवेरे उठना और अल्लाह को याद करने के साथ ही पांचो वक्त की नमाज रोजेदार को अल्लाह की इबादत का मौका दिलाती है। रमजान की शुरूआत भी चांद से ही होती है और रमजान पूरे होने पर ईद का जब चांद निकलता है तो सबके चेहरे पर खुशी छा जाती है। दरअसल रमजान के सकुशल बीतने की खुशी में ही अल्लाह को शुक्रिया अदा करने के लिए ही ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। वही रमजान अल्लाह के नेक बन्दो की खिदमत का भी मुबारक मौका भी है ।नमाज के बाद अल्लाह ने जो दूसरी इबादत मुसलमानों के लिए अनिवार्य की है वह है रोजा। रोजे से मुराद ये है कि रमजान के महीने में 30 दिन तक सुबह से शाम तक खाना-पीना नहीं होता। नमाज की तरह ही इबादत रोजा भी अल्लाह के भेजे सभी पैगंबरों के मानने वालों पर फर्ज हैं और आज भी अधिकतर धर्मों में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। वास्तव में इस्लाम का रोजे से तात्पर्य यह है कि बंदा अपना जीवन रब की इच्छा और उसके आदेशों को मानते हुए गुजार दे। साल भर में रमजान महीने के रोजे इसी मकसद का प्रशिक्षण हैं।इस्लामिक कैलेंडर के नौवें महीने को रमज़ान का महीना कहा जाता है। इस महीने में तीस दिनों तक रोज़ा रखना प्रत्येक मुस्लिम के लिए अनिवार्य बताया गया है। मुसलमानों के लिए यह पाक रोज़ा का महीना होता है। रोज़ा के लिए जो अरबी शब्द बोला जाता है, उसे 'सॉम' कहते है,इसका शाब्दिक अर्थ है 'संयम करना।' सॉम शब्द रमजान के महीने की सच्ची भावना को दर्शाता है। जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक रोज़ा रखना होता है। रोज़े का मतलब होता है व्यक्ति के मन को अध्यात्म से जोड़ना। जिससे उसके अंदर कृतज्ञता और स्नेह का ऐसा भाव उत्पन्न हो। जिससे व्यक्ति पूरे वर्ष संयम और नियम से चल पाए। सूर्यास्त के एक दम बाद रोज़ा खोला जाता है। रोजेदार खजूर और पानी के साथ इफ़्तार करते हैं। क्योंकि हज़रत मुहम्मद साहब अपना रोज़ा खजूर और पानी से खोलते थे। रमज़ान में मुस्लिम समाज एक अतिरिक्त नमाज़ पढ़ते हैं जिन्हें तरावीह कहा जाता है। तरावीह की नमाज़ रात की नमाज़ के बाद मस्जिद में सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है। इस नमाज़ में पूरा कुरआन रमज़ान के महीने के अंदर पढ़ा जाता है। रमज़ान में कुरआन पढ़ने पर अत्यधिक ज़ोर दिया गया है। ताकि प्रत्येक रोज़ेदार इस पर चिंतन कर सके। आज कल के हालात के चलते विश्वभर के मुस्लिम चिंतित हैं कि वे तरावीह की नमाज़ कैसे अदा करेंगे। लेकिन यह कोई चिंता का विषय नहीं। हदीस की किताब अल-बुख़ारी में आता है की इस्लाम के पैगंबर तरावीह की नमाज़ अकेले घर पर पढ़ते थे, मस्जिद में नहीं।एक माह तक रोजा रख चुके लोग नये नये कपडे पहनकर ईद की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह जाते है। ईदगाह में नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है।लेकिन इस बार कोरोना के चलते बिना गले मिले ही दिल से एक दूसरे को दुआएं देंगे तो अच्छा रहेगा। रमजान के बाद आने वाली ईद उल फितर की शुरूआत जगं ए बदर के बाद सन 624 ईसवी के पैगम्बर मौहम्मद साहब द्वारा ईद उल फितर मनाने से मनाने से हुई थी। रमजान साल का एक अनूठा महिना होता है। इस महिने में हर मुस्लमान जंहा ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह की रहमत में गुजारना चाहता है। वही वह स्वयं को सुधारने व खुदा के बन्दो के चेहरो पर रौनक लाने के लिए उनके हर गम में शरीक होता है। जो खुदा के बन्दे पैसो से मोहताज है, भूखे है ,लाचार है उनकी हर हाल में मदद कर उन्हे बराबरी पर लाने की कौशिश की जाती है। रमजान के महिने में हर दिन पाक साफ रहने की हिदायत है ताकि रोजेदार हर तरह के गुनाहो से दूर रहे। आपसी भाईचारे से रहना सीखे।

रेलवे सुधारों पटरी पर नई एक्सप्रेस ऑन-बोर्ड सेवाओं से लेकर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों तक भारत के परिवहन परिदृश्य में ऐतिहासिक परिवर्तन - अर्थात सुधारों की पटरी भारतीय रेल नई रफ्तार लगाने के लिए तत्पर है

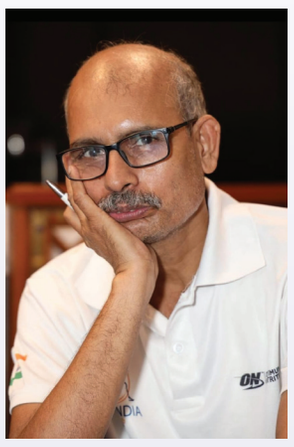

विनोद कुमार सिंह,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार

भारतीय रेल केवल एक परिवहन प्रणाली नहीं है,बल्कि यह भारत की आर्थिक,सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की धमनियों में प्रवाहित होने वाला जीवन प्रवाह है। ब्रिटिश काल में बिछी रेल पटरियों से लेकर स्वतंत्र भारत के औद्योगिक और सामाजिक पुनर्निर्माण तक,रेल ने देश को जोड़ा,गति दी और एक राष्ट्र की भौगोलिक विविधताओं को एक साझा अनुभव में पिरोया।आज जब भारत 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक में आगे बढ़ रहा है,तब भारतीय रेल स्वयं को एक पारंपरिक परिवहन सेवा से बदलकर एक आधुनिक, तकनीक-संचालित,लॉजिस्टिक्स-सक्षम और ग्राहक-केंद्रित परिवहन इकोसिस्टम के रूप में पुनर्परिभाषित कर रही है। रेल मंत्रालय द्वारा घोषित 'बेहतर ऑन-बोर्ड सेवाएं' और 'गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों के माध्यम से रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स' की रणनीति,भारतीय रेल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखी जा सकती है। यह सुधार केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं है,बल्कि यह भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर,औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला,और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला कदम है।रेलयात्रा अनुभव के संदर्भ में भारतीय रेल लंबे समय से आम नागरिकों की जीवनरेखा रही है,परंतु यात्रियों की अपेक्षाएं समय के साथ बदलती गई हैं।स्वच्छता,आराम,समय बद्धता और सेवा गुणवत्ता अब केवल सुविधा नहीं बल्कि अधिकार के रूप में देखी जाने लगी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में रेलवे द्वारा सामान्य डिब्बों सहित सभी कोचों में निरंतर सफाई की व्यवस्था लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक महत्व रखता है। सामान्य श्रेणी के यात्रियों को अब तक सुविधाओं के मामले में अक्सर उपेक्षित माना जाता रहा है,किंतु वर्तमान सुधारों का केंद्रबिंदु यही वर्ग है,जो भारतीय रेल के सामाजिक लोकतंत्र का प्रतीक है। रेलवे द्वारा बेहतर लिनन प्रबंधन और कोच सफाई के लिए सेवा प्रदाता की पहचान तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव,भारतीय रेल के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है।एआई सक्षम निगरानी प्रणाली केवल सफाई की निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी,बल्कि यह सेवा गुणवत्ता,शिकायत निवारण और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक डेटा-आधारित प्रणाली के रूप में विकसित हो सकती है।इससे रेलवे प्रशासन के निर्णय अधिक वैज्ञानिक,पारदर्शी और उत्तरदायी बनेंगे।रेलवे सुधारों का दूसरा और अधिक व्यापक आयाम रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स और मल्टी-मॉडल टर्मिनलों के रूप में सामने आया है।वर्तमान में देश में 124 मल्टी- मॉडल टर्मिनल कार्यरत हैं,जिन्हें अब 'कार्गो-प्लस- प्रोसेसिंग हब' के रूप में विकसित करने की योजना है।इसका अर्थ यह है कि रेल टर्मिनल केवल माल लोड और अनलोड करने का स्थान नहीं रहेंगे,बल्कि वे मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग ,भंडारण ,प्रसंस्करण और वितरण के केंद्र बनेंगे।यह अवधारणा विकसित देशों के लॉजिस्टिक्स मॉडल के अनुरूप है, जहां परिवहन केंद्र आर्थिक गतिविधियों के क्लस्टर के रूप में कार्य करते हैं।इसके अतिरिक्त, 500 से अधिक गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों की योजना भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न परिवहन माध्यमों—रेल, सड़क, जलमार्ग और वायु मार्ग—के एकीकरण का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है,भारतीय रेल उसमें केंद्रीय भूमिका निभाने जा रही है।रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स लागत-कुशल,ऊर्जा-कुशल और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ है। भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक संरचना वाले देश में, जहां माल परिवहन की लागत सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है,रेल आधारित लॉजिस्टिक्स सुधार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। लॉजिस्टिक्स सुधारों का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि,उद्योग,व्यापार और निर्यात क्षेत्र पर पड़ेगा।कृषि उत्पादों की समयबद्ध ढुलाई,औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार माल का वितरण और ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग ऑल इन क्षेत्रों में रेल आधारित कार्गो नेटवर्क एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।विशेष रूप से भारत के अंतर्देशीय और दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा,जहां सड़क और अन्य परिवहन साधन सीमित हैं। भारतीय रेल द्वारा फील्ड लर्निंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के आधार पर इन सुधारों को पूरे नेटवर्क में लागू करने की योजना, प्रशासनिक परिपक्वता और व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत है। अक्सर बड़े पैमाने पर लागू की गई योजनाएं जमीनी स्तर पर असफल हो जाती हैं,किंतु चरणबद्ध कार्यान्वयन और फील्ड अनुभव से सीखने की रणनीति नीति निर्माण में आधुनिक शासन मॉडल को दर्शाती है।रेलवे सुधारों का यह अभियान केवल तकनीकी या प्रशासनिक सुधार नहीं है,बल्कि यह एक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का वाहक है।भारतीय रेल लोकतांत्रिक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक संस्थान है,जहां अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण,सभी एक ही डिब्बे में यात्रा करते हैं।इसलिए जब सामान्य कोचों की सफाई और सेवा गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाती है,तो यह सामाजिक न्याय और समावेशन की भावना को भी प्रतिबिंबित करता है।डिजिटल निगरानी,एआई आधारित प्रणाली और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सफाई और लिनन प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारने का उद्देश्य केवल दृश्य स्वच्छता नहीं,बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और यात्री संतोष को बढ़ाना भी है। स्वच्छता केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का प्रश्न है।कोविड-19 महामारी के बाद स्वच्छता और स्वास्थ सुरक्षा के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता बढ़ी है , भारतीय रेल का यह कदम उसी चेतना का परिणाम है।भारतीय रेल द्वारा लॉजिस्टिक्स हब के रूप में टर्मिनलों के विकास से निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे।सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से आधुनिक वेयरहाउसिंग,कोल्ड स्टोरेज,प्रोसेसिंग यूनिट्स और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किए जा सकते हैं।इससे रोजगार सृजन,क्षेत्रीय विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की लागत लगभग 13-14 प्रतिशत आंकी जाती है, जो विकसित देशों की तुलना में अधिक है।रेल आधारित लॉजिस्टिक्स सुधारों से इस लागत में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि यह लक्ष्य सफल होता है,तो भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे,निर्यात बढ़ेगा और 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों को ठोस आधार मिलेगा।रेलवे सुधारों का यह अभियान उस व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है,जिसमें भारत अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक,टिकाऊ और डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाई-स्पीड रेल,समर्पित माल गलियारे, स्टेशन पुनर्विकास, .वंदे भारत ट्रेनें,और डिजिटल टिकटिंग -ये सभी पहलें एक समग्र परिवहन क्रांति की ओर संकेत करती हैं।ऑन-बोर्ड सेवाओं में सुधार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार इस क्रांति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।इस परिवर्तन की सफलता प्रशासनिक क्षमता,तकनीकी कार्यान्वयन, वित्तीय संसाधनों और नागरिक सहभागिता पर निर्भर करेगी।सेवा प्रदाताओं की पारदर्शी नियुक्ति, एआई सिस्टम की विश्वसनीयता, डेटा सुरक्षा,और जमीनी स्तर पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण - ये सभी कारक सुधारों की स्थिरता और प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। भारतीय रेल के सुधारों की यह नई एक्सप्रेस केवल पटरियों पर दौड़ती ट्रेन नहीं,बल्कि भारत के विकास पथ पर दौड़ती परिवर्तन की रेलगाड़ी है। यह सुधार भारत के आम नागरिक को बेहतर यात्रा अनुभव, उद्योग को कुशल लॉजिस्टिक्स,और राष्ट्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जब सामान्य कोच का यात्री स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में यात्रा करेगा,जब किसान का उत्पाद समय पर बाजार पहुंचेगा,जब उद्योग को कच्चा माल सस्ती और तेज़ गति से मिलेगा,और जब भारत का निर्यात वैश्विक बाजार में नई पहचान बनाएगा - तब यह कहा जा सकेगा कि भारतीय रेल ने केवल पटरियां नहीं बिछाईं,बल्कि विकसित भारत की राह भी प्रशस्त की।भारतीय रेल के इस परिवर्तन कारी अभियान को केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं,बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जाना चाहिए।यह मिशन भारत की गति, दिशा और नियति को आकार देने वाला है।रेल की सीटी केवल स्टेशन पर आगमन का संकेत नहीं,बल्कि भारत के भविष्य के आगमन की उद्घोषणा है। वही ऑन-बोर्ड सेवाओं से लेकर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों तक भारत के परिवहन परिदृश्य में ऐतिहासिक परिवर्तन - अर्थात सुधारों की पटरी भारतीय रेल नई रफ्तार लगाने के लिए तत्पर है ।

टी-20 वर्ल्डकप-साउथ अफ्रीका की लगातार चौथी जीत

यूएई को छह विकेट से हराया

नईदिल्ली(एजेंसी)। साउथ अफ्रीका ने टी-20 वर्ल्ड कप के 34वें मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 6 विकेट से हरा दिया। टीम की इस वर्ल्डकप में लगातार चौथी जीत है। वहीं, यूएई की तीसरी हार है। साउथ अफ्रीका सुपर-8 में पहले ही पहुंच चुकी है और यूएई बाहर हो चुकी है। दोनों टीमों का यह आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला था। साउथ अफ्रीका ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। यूएई ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाए। 123 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 36, रयान रिकेल्टन ने 30, ऐडन मार्करम ने 28 और क्विंटन डी कॉक ने 14 रन बनाए। जेसन स्मिथ (3) और ट्रिस्टन स्टब्स (6) नाबाद रहें।

यूएई के लिए अलीशान शराफू ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान मुहम्मद वसीम 22, ओपनर अर्यांश शर्मा ने 13 और मुहम्मद अरफान ने 11 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश ने 3 और एनरिक नॉर्त्या ने 2 विकेट लिए। जॉर्ज लिंडे को 1 विकेट मिला। कॉर्बिन बॉश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

दोहा ओपन 2026

अल्कारेज की शानदार शुरुआत, हार्ड-कोर्ट पर दर्ज की 150वीं जीत

दोहा (एजेंसी)। क्वाटर ओपन में विश्व नंबर-1 अल्कारेजने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के बाद अल्कारेज़ ने पहले दौर में फ्रांस के आर्थर को 6-4, 7-6 (5) से हराया। इस जीत के साथ 22 वर्षीय स्पेनिश स्टार ने टूर स्तर पर अपनी 150वीं हार्ड-कोर्ट जीत दर्ज की और 2026 सीजन में अपना रिकॉर्ड 8-0 कर लिया।

संघर्षपूर्ण मुकाबला, टाई-ब्रेक में दिखाया दम- दूसरे सेट में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। अल्कारेज़ को दो सेट प्वाइंट बचाने पड़े, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखते हुए टाई-ब्रेक में जीत हासिल की।

मैच के बाद अल्कारेज़ ने कहा, यह आसान नहीं था। आर्थर खतरनाक खिलाड़ी हैं। पहले राउंड में कोई भी उनके खिलाफ नहीं खेलना चाहता। मैं खुश हूं कि मुश्किल पलों में शांत और सकारात्मक रहा।

आगे की राह- संभावित बड़े मुकाबले- पिछले साल दोहा में क्वार्टरफाइनल में हारने वाले अल्कारेज़ इस बार बेहतर प्रदर्शन की कोशिश में हैं। दूसरे दौर में उनका सामना फ्रांस के Valentin Royer से होगा। फाइनल में उनकी भिड़ंत दूसरे वरीय Jannik Sinner से हो सकती है, जो दोनों के बीच 17वां मुकाबला होगा। क्वार्टरफाइनल में उनका सामना 2024 चैंपियन Karen Khachanov से भी हो सकता है।

67 साल में जम्मू-कश्मीर पहली बार फाइनल में

रणजी ट्रॉफी

● बंगाल को 6 विकेट से हराया ● आकिब नबी ने 9 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद शमी के 9 विकेट बेकार साबित हुए

नईदिल्ली (एजेंसी)। कल्याणी में खेले गए रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने दो बार की पूर्व चैंपियन बंगाल को 6 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। जीत के लिए मिले 126 रनों के छोटे लक्ष्य को टीम ने चौथे दिन 34.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भले ही बंगाल यह सेमीफाइनल मुकाबला हार गया हो। लेकिन भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है। शमी ने पहली पारी में 8 तो दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। इस तरह उन्होंने पूरे मैच में कुल 9 विकेट झटके।

वंशज शर्मा ने 43 रन बनाए, जबकि आईपीएल स्टार अब्दुल समद 30 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत तक पहुंचाया। इस जीत के हीरो तेज गेंदबाज आकीब नबी रहे, जिन्होंने मैच में कुल 9 विकेट लेकर बंगाल की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने पहली पारी में 42 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान भी दिया।

समद की आक्रामक बैटिंग और वंशज का छक्का

मैच के चौथे दिन जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 83 रनों की जरूरत थी और उनके 8 विकेट सुरक्षित थे। सुबह के सत्र में शुभम पुंडीर (27) और कप्तान पारस डोगरा (9) जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया था। इसके बाद अब्दुल समद और 22 साल के युवा वंशज शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच 55 रनों की अटूट साझेदारी हुई। समद ने अपनी 27 गेंदों

की पारी में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर बंगाल के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। मैच का अंत वंशज शर्मा ने मुकेश कुमार की गेंद पर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर किया।

बंगाल के इंटरनेशनल स्टार्स फेल रहे- बंगाल की टीम में मोहम्मद शमी, आकाश दीप, मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद जैसे चार इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल थे। इसके बावजूद टीम दूसरी पारी में महज 99 रनों पर सिमट गई। बंगाल ने पहली पारी में 328 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 302 रन बनाए। दूसरी पारी में अकीब नबी की घातक गेंदबाजी के सामने बंगाल का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। आकाश दीप ने दूसरी पारी में 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन वे हार नहीं टाल सके।

1959 से सफर शुरू हुआ, 44 साल बाद मिली थी पहली जीत- जम्मू-कश्मीर ने पहली बार 1959-60 के सीजन में रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया था। शुरुआत में इस टीम को एक कमजोर टीम माना जाता था। टीम को अपनी पहली जीत दर्ज करने में ही 44 साल लग गए थे, जब 1982-83 में उन्होंने सर्विसेज को हराया था।

2013-14 में टीम पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंची थी। इस सीजन में कोच अजय शर्मा और कप्तान पारस डोगरा के मार्गदर्शन में टीम ने मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और हैदराबाद जैसी बड़ी टीमों को हराकर अपना लोहा मनवाया।

अकीब नबी ने इस सीजन 55 विकेट लिए

तेज गेंदबाज अकीब नबी के लिए यह सीजन किसी सपने जैसा रहा है। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ 12 विकेट लेने वाले नबी ने सेमीफाइनल में भी 9 विकेट चटकाए। इस सीजन में उनके कुल विकेटों की संख्या 55 हो गई है और उनका औसत 13 से भी कम का रहा है। गेंदबाजी के अलावा उन्होंने पहली पारी में 42 रनों का अहम योगदान भी दिया था। मैच के बाद नबी ने कहा, पिछली बार हम क्वार्टर फाइनल में चूक गए थे।

कप्तान पारस डोगरा रणजी में 10 हजार बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज- 41 साल के कप्तान पारस डोगरा ने मैच के दौरान रणजी ट्रॉफी में अपने 10,000 रन पूरे किए। वे वसीम जाफर के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी से होते हुए जम्मू-कश्मीर पहुंचे डोगरा ने पहली पारी में 58 रनों की जुझारू पारी खेली थी, जिसने जीत की नींव रखी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी बधाई

इस ऐतिहासिक जीत पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह खिलाड़ियों की मेहनत और कोचिंग स्टाफ के अनुशासन का नतीजा है। जम्मू-कश्मीर की टीम ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार किया है। मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे खिलाड़ी भारतीय टीम में भी अहम भूमिका निभाते दिखेंगे।

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। वनडे क्रिकेट में 6 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम का दबदबा जगजाहिर है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में उनका रिकॉर्ड उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। वनडे के सुल्तान माने जाने वाले कंगारू इस छोटे फॉर्मेट में लंबे समय तक संघर्ष करते दिखे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही टीम है जिसने वनडे फॉर्मेट में पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखा है। टी20 फॉर्मेट आते ही वनडे के सुल्तान एक कमजोर टीम लगने लगती है।

ऑस्ट्रेलिया का टी20 वर्ल्ड कप सफर

ऑस्ट्रेलिया ने अब तक के सभी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, लेकिन उन्हें अपनी पहली और इकलौती ट्रॉफी के लिए 14 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। किसी ने सोच तक नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बात करें मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के बारे में तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ग्रुप स्टेड से ही बाहर हो गई। किसी ने सोचा तक नहीं

वनडे के चैंपियन टी20 में हैं फिसड्डी

होगा कि उन्हें जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ेगा।

ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में साल 2021 रहा सबसे सफल- 2021 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपवाद रहा। एरोन फिंच की कप्तानी में टीम ने दुबई में मिचेल मार्श और एडम जाम्पा के शानदार प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला टी20 खिताब जीता। हालांकि, 2022 में अपने ही घर में खेलते हुए वे सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए, जिसने फिर से उनकी टी20 साख पर सवाल खड़े कर दिए। 2024 में तो उनकी टीम अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम से खिलाफ हार गई थी।

विराट से तुलना करना बंद करो...

● बाबर आजम के घटिया शॉट पर भड़का भारतीय दिग्गज, कर डाली ये मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान की टीम 176 रन के टारगेट का पीछा करते हुए महज 114 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और 61 रन से मुकाबला हार गई थी।एक समय था जब पाकिस्तान के 13 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के लिए क्रीज पर उनके स्टार खिलाड़ी बाबर आजम मौजूद थे, जिनपर पाकिस्तानी फैंस को भरोसा था कि वो वहां से मैच जितवा सकते हैं। लेकिन बाबर आजम ने अक्षर पटेल के खिलाफ घुटना टेका और बड़ी हिट लगाने की कोशिश की। वह गेंद को पूरी तरह से मिस कर गए और शर्मनाक तरीके से बोल्ड हो गए। बाबर 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी टीम को और मुश्किल में डाल गए। इसपर अब भारत के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने बाबर की आलोचना की है।

दिनेश कार्तिक ने की बाबर आजम की आलोचना- दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज पर कहा, लंबे समय से एक तुलना जो होती आ रही है और मुझे सही नहीं लगती। विराट कोहली और बाबर आजम। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि विराट कोहली पारी की शुरुआत में ऐसा शॉट खेलेंगे।

कारों में फिजिकल स्विच को अनिवार्य बनाएगा चाइना

नई दिल्ली। कारों के लिए चाइनीज सरकार अब महत्वपूर्ण सेफ्टी फंक्शन्स के लिए फिजिकल स्विच को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम ड्राइवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। हाल के वर्षों में टेस्ला, बीवायडी और शाओमी जैसी कंपनियों ने क्लीन, मिनिमलिस्ट और स्क्रीन-डॉमिनेटेड केबिन पेश किए हैं, जिनमें फिजिकल कंट्रोल्स बेहद कम होते हैं। कई मॉडल्स में तो इमर्जेंसी में इस्तेमाल होने वाला हैजर्ड लाइट बटन भी टचस्क्रीन पर दिया जा रहा है, जिससे सॉफ्टवेयर-आधारित सिस्टम पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। यह प्रवृत्ति ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ाती है।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार चीन का उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अब टर्न सिग्नल, हैजर्ड लाइट, गियर सेलेक्टर और इमर्जेंसी कॉलिंग जैसे फीचर्स के लिए अनिवार्य रूप से अलग और कम से कम 10 मिमी गुणा 10 मिमी आकार वाले फिजिकल बटन्स रखने को बाध्य करेगा। इससे कार निर्माताओं को अपने मॉडल्स का इंटीरियर फिर से डिजाइन करना होगा और टचस्क्रीन कंट्रोल्स को हटा कर पारंपरिक बटन वापिस जोड़ने पड़ेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान टचस्क्रीन का उपयोग ड्राइवर के रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है, जो हाई-स्पीड ड्राइविंग में खतरनाक साबित होता है। सड़क से पलभर के लिए नजर हटाने से भी लेन में बने रहने की क्षमता प्रभावित होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। अगर स्क्रीन धीमी चले या हैंग हो जाए, तो स्थिति और अधिक खतरनाक हो सकती है। इन्हीं जोखिमों को देखते हुए चीन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सरकार चाहती है कि तकनीक का उपयोग बढ़े, लेकिन ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर कम न हो। नए नियम लागू होने पर गाड़ियों में दोबारा से फिजिकल कंट्रोल्स का दौर लौटता दिख सकता है, जिससे ड्राइविंग और यात्राएं अधिक सुरक्षित बन सकेंगी।

चांदी आज 4 हजार बढ़कर 2.37 लाख पर पहुंची:सोना 291 सस्ता होकर 1.52 लाख हुआ

नई दिल्ली। चांदी की कीमत में आज यानी 18 फरवरी को बढ़त और सोने की कीमत में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, एक किलो चांदी 3,834 रुपए बढ़कर 2.37 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले कल ये 2.33 लाख रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 291 रुपए सस्ता होकर 1.52 लाख रुपए पर पहुंच गया है। सर्राफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।

2025 में 57 हजार रुपए महंगा हुआ था सोना- 2025 में सोना 57 हजार (75%) बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76 हजार का था, जो 31 दिसंबर 2025 को 1.33 लाख रुपए हो गया।

चांदी इस दौरान 1.44 लाख (167%) बढ़ी। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी 86 हजार की थी, जो साल के आखिरी दिन 2.30 लाख प्रति किलो हो गई।

सर्राफाः सोना-चांदी 6 माह में कम से कम 10% और सस्ते हो सकते हैं- इक्विनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर और एमडी जी. चोक्कालिंगम ने कहा कि सोने-चांदी के साथ ही कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स अत्यधिक अस्थिर रहेंगे। अगले 6 महीनों में इनके दाम कम से कम 10% और घट सकते हैं। वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी, क्रिप्टोकरेंसी और टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट जैसे जोखिम कमोडिटी की कीमतों पर असर डाल सकते हैं।

प्रल्हाद जोशी ने कहा-देश की गैर जीवाश्म बिजली क्षमता 272 गीगावाट के पार

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को कहा कि भारत की गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 272 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है, जिसमें 141 गीगावाट सौर तथा 55 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक भारत और ब्रिटेन ने आज भारत-यूके अपतटीय पवन कार्यबल लॉन्च किया, जिसका मकसद विजन 2035 के तहत अपनी बड़ी स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के हिस्से के तौर पर अपतटीय पवन विकास में सहयोग को तेज करना है। इस अवसर पर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून भी मौजूद थीं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत-ब्रिटेन अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल की शुरुआत के मौके पर यह जानकारी दी। इस अवसर पर प्रल्हाद जोशी ने कहा कि अपतटीय पवन ऊर्जा देश के स्वच्छ, आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य का मजबूत स्तंभ बन सकती है। कार्यबल की औपचारिक शुरुआत के मौके पर जोशी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 35 गीगावाट से अधिक सौर तथा 4.61 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल किया। यह उपलब्धिक निर्धारित लक्ष्य से पांच वर्ष पहले हासिल की गई। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट नीति, संस्थागत समन्वय तथा निवेशकों और उद्योग के भरोसे को दर्शाते हैं। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा तथा 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंत्री ने कहा कि आज भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता 272 गीगावाट से अधिक है जिसमें सौर से 141 गीगावाट और पवन से 55 गीगावाट है...। हमारी व्यापकता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दो साल से कम समय में करीब 30 लाख परिवारों को 'रूफटॉप सोलर' की सुविधा मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत 21 लाख पंपों का सौरकरण किया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)